दक्ष®

वर्ष 2016, 2015 एवं 2011 के पेपर्स सम्पूर्ण हल एवं व्याख्या सहित

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)

20 June 2023 को जारी नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार

A Complete Book for

जूनियर अकाउण्टेन्ट

(Junior Accountant)

भारतीय अर्थशास्त्र

(Indian Economics)

PAPER-2

- भारत एवं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आंकड़ों का अध्यायवार समावेश
- 1100 से अधिक विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का समावेश

M. K. Yadav

Buy Online at : WWW.DAKSHBOOKS.COM

प्रकाशक :

परितोष वर्धन जैन

कॉलेज बुक सेन्टर

- A-19, सेठी कॉलोनी, जयपुर-302 004

© सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

लेजर टाईपसैटिंग :

पूजा एण्टरप्राईजेज़

जयपुर

मुद्रक :

के.डी. प्रिन्टर्स

जयपुर।

Completely Changed & Updated Version

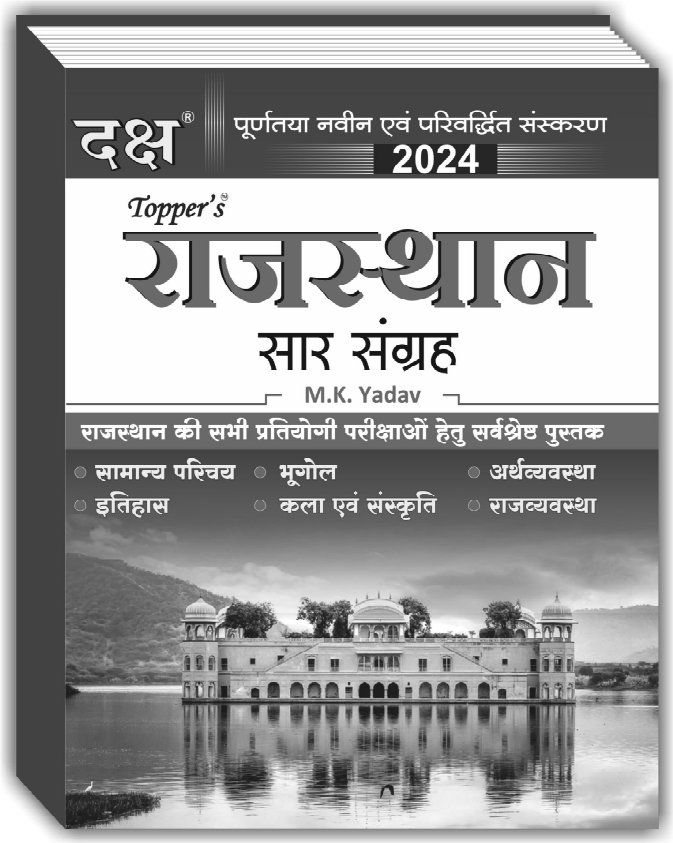

राजस्थान G.K. की Best Book

यह Book आपके selection को easy बनायेगी

Code No.: D-698

- प्रकाशक की अनुमति के बिना इस पुस्तक के किसी भी अंश का किसी भी प्रणाली के सहारे पुन:उत्पत्ति का प्रयास अथवा किसी भी तकनीकी तरीके (इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फॉटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, डिजिटल, वेब) के माध्यम से अथवा इस पुस्तक का नाम, टाईटल, चित्र, रेखाचित्र, नक्शे, डिजाईन, कवर डिजाईन, सैटिंग, शिक्षण-सामग्री, विषय-वस्तु, पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी भाषा में हूबहू या तोड़-मरोड़ कर या अदल-बदल कर प्रकाशन या वितरण नहीं किया जा सकता है। इस पुस्तक के प्रतिलिप्याधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं।
- पुस्तक का कम्पोजिंग कार्य कम्प्यूटर द्वारा कराया गया है। पुस्तक के लेखन व प्रकाशन कार्य में लेखक, प्रूफ रीडर, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरतने के बावजूद भी अधूरी या पुरानी जानकारी का होना/कुछ ग़लतियों/कमियों का रह जाना मानवीय भूलवंश सम्भव है, जिसके लिए पुस्तक प्रकाशन से जुड़े मुद्रक, लेखक एवं प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होंगे। पाठकों के सुझाव सादर आमंत्रित हैं।
- सभी विवादों का न्यायक्षेत्र जयपुर (राज.) होगा।

प्राक्कथन

प्रिय पाठकों,

वर्तमान दौर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षार्थियों को सामान्यतः दो–तीन माह से अधिक समय नहीं मिलता। इतने कम समय में यदि परीक्षार्थी गलत स्रोत का चुनाव करता है तो वह सफलता से वंचित रह जाता है। आज के भौतिकतावाद और जल्दी पैसा कमाने की होड़ ने पुस्तकों की गुणवत्ता खराब कर दी है। ऐसे में मेरा प्रयास है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इस खण्ड के द्धारा प्रामाणिक एवं सटीक जानकारी प्रतियोगी परीक्षार्थियों तक पहुँचाऊँ। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक **Jr. Accountant & TRA** की परीक्षा में परीक्षार्थियों की उम्मीद और आवश्यकता दोनों पर खरी उतरेगी। यद्यपि इस पुस्तक में भारत व राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बखूबी समझाने का प्रयास किया गया है फिर भी पाठकों के सुझाव सदैव सादर आमंत्रित हैं।

शुभकामनाओं सहित!

Mahendra Kumar Yadav

YouTube : PRIME STUDY CENTRE

SYLLABUS

INDIAN ECONOMICS

- Indian Economy - Features and problems, Economic policy, Industrial policy, Monetary policy and Fiscal policy of India.
- Meaning, objectives and importance of economic planning in India. Planning Commission and NITI Aayog.
- Population Explosion-Causes, effects and remedies. Relation between population and economic growth.
- Role and significance of agriculture in Indian economy. Sources of agriculture finance and recent trends in agriculture marketing.
- Industrial growth and prospects in India.
- Inflation - Causes, effects and remedies.
- Public sector in India: Role, Progress and Problems.
- Impact of globalization and liberalization on agriculture and industry.
- Role of Multi-national corporations in Indian economy.
- Foreign Trade - Volume, composition and direction.
- National Income - Concept, computation methods and distribution.
- Economy of Rajasthan - Basic features.
- Tourism in Rajasthan.

दक्ष Jr. Accountant बुक की कहानी, जानें Selected विद्यार्थियों की जुबानी

भारतीय अर्थव्यवस्था विषय की यह पुस्तक बहुत ही क्रमबद्ध एवं रुचिकर कन्टेन्ट के अनुसार लिखी गई है, प्रतियोगी परीक्षार्थियों की सफलता में दक्ष पुस्तक का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

राजेन्द्र कुमार शर्मा
Selected
Jr. Accountant 2013

जूनियर अकाउण्टेन्ट एग्जाम में अर्थशास्त्र अति महत्वपूर्ण विषय है, अर्थशास्त्र विषय की तैयारी हेतु दक्ष भारतीय अर्थव्यवस्था पुस्तक श्रेष्ठ पुस्तक है।

देवेन्द्र ज्यानी
Selected
Jr. Accountant 2013

प्रतियोगी परीक्षार्थियों को परीक्षा के दृष्टिकोण से जिस महत्वपूर्ण कन्टेन्ट की आवश्यकता रहती है, वह कन्टेन्ट इस पुस्तक में दिया गया है। यह पुस्तक आपके सलेक्शन में मील का पत्थर साबित होगी।

प्रियंका मीणा
Selected
Jr. Accountant 2013

जूनियर अकाउण्टेन्ट परीक्षा के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की यह पुस्तक पूर्व में भी विद्यार्थियों हेतु मील का पत्थर साबित हुई है, विद्यार्थी इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें।

पिंकी यादव
Selected
Jr. Accountant 2013

दक्ष पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी सभी परीक्षाओं में सफलता की कसौटी पर खरी उतरती है, सभी विद्यार्थियों को यह सलाह देना चाहूँगा कि ये Book जरूर पढ़ें।

रामनिवास यादव
Selected
Jr. Accountant 2013

इस पुस्तक में जूनियर अकाउण्टेन्ट परीक्षा 2011 एवं जूनियर अकाउण्टेन्ट परीक्षा 2013 (आयोजित 2015, 2016) के प्रश्नों का पूर्णतया हल दिया गया है। यह पुस्तक विद्यार्थियों को निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी।

पूजा यादव
Selected
Jr. Accountant 2013

दक्ष भारतीय अर्थव्यवस्था बुक में थ्योरी के साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों का समावेश होना अतिउपयोगी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जूनियर अकाउण्टेन्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था विषय में ये पुस्तक विद्यार्थियों को अवश्य सफलता दिलाएगी।

करण सिंह यादव
Selected
Jr. Accountant 2013

अर्थशास्त्र विशेषज्ञ एम. के. यादव के मार्गदर्शन में लिखित सभी पुस्तकों ने विद्यार्थियों की सफलता में अतिमहत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

मनमोहन शर्मा
Selected
Jr. Accountant 2013

अनुक्रमणिका

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पेज नम्बर

❖ कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
कम्प्यूटर के मूल सिद्धांत 4 दिसम्बर, 2016 ..... P-1—P-4

❖ कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
कम्प्यूटर के मूल सिद्धांत 2 अगस्त, 2015 ..... P-5—P-7

❖ कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
कम्प्यूटर के मूल सिद्धांत 3 जनवरी, 2011 ..... P-8—P-10

1 भारतीय अर्थव्यवस्था
[Indian Economy]
विशेषताएँ एवं समस्याएँ, भारत की आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति एवं राजकोषीय नीति
[Features & Problems, Economic Policy, Industrial Policy & Fiscal Policy of India] 1

- ❖ भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ (Features of Indian Economy) 1
- ❖ भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष समस्याएँ (Problems before the Indian Economy) 2
- ❖ आर्थिक नीति (Economic Policy) 2
- ❖ भारत की औद्योगिक नीति 3
- ❖ नई आर्थिक नीति (LPG) 5
- ❖ राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) 5
- ❖ सरकार का बजट 5
- ❖ सरकार की प्राप्तियाँ एवं व्यय 6
- ❖ विभिन्न सरकारी घाटे 8
- ❖ भारत के वित्त आयोग 11
- ❖ भारत सरकार की निधियाँ 11
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 11

2 भारत में नियोजन, योजना आयोग एवं नीति आयोग
[Economic Planning in India, Planning Commission & NITI Aayog]
अर्थ, उद्देश्य एवं महत्त्व (Meaning, Objectives and Importance) 15

- ❖ भारत में नियोजन का अर्थ (Meaning f Planning in India) 15
- ❖ नियोजन के उद्देश्य (Objectives of Planning) 15
- ❖ नियोजन का महत्त्व (Importance of Planning) 16
- ❖ भारत में नियोजन का इतिहास (History of Planning in Inida) 16
- ❖ भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत नियोजन 17
- ❖ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया (NITI) आयोग 21
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 22

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पेज नम्बर

3 जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या और आर्थिक संवृद्धि के बीच संबंध
[Population Explosion, Relation between Population & Economic Growth] 25
- ❖ कारण, प्रभाव एवं उपचार (Causes, Effects and Remedies) 25
- ❖ जनसंख्या विस्फोट 25
- ❖ भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण 26
- ❖ जनसंख्या विस्फोट के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव 26
- ❖ जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के उपचार 27
- ❖ राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 27
- ❖ जनसंख्या और आर्थिक संवृद्धि के बीच संबंध (Relation between population and economic growth) 27
- ❖ मानव विकास सूचकांक 2022 28
- ❖ जनसंख्या से संबंधित पारिभाषिक शब्द 28
- ❖ माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत 29
- ❖ जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत 29
- ❖ जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत 30
- ❖ जनगणना 2011 के महत्त्वपूर्ण तथ्य 30
- ❖ जनसंख्या घनत्व 31
- ❖ लिंगानुपात 31
- ❖ साक्षरता दर 32
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 32

4 भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका एवं महत्त्व/कृषि वित्त के स्रोत एवं कृषि विपणन की नई प्रवृत्तियाँ
[Role and Significance of Agriculture in Indian Economy Sources of Agriculature Finance and Recent Trends in Agriculture Marketing] 34
- ❖ भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका एवं महत्त्व (Role and Significance of Agriculture in Indian Economy) . 34
- ❖ भारतीय कृषि की विशेषताएँ 35
- ❖ कृषि वित्त हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयास 36
- ❖ कृषि विपणन की नई प्रवृत्तियाँ 37
- (Recent Trends in Agriculture Marketing) 37
- ❖ भारत में कृषि विपणन सुदृढ़ीकरण के सरकारी प्रयास 38
- ❖ सहकारी विपणन (Co-Operative Marketing) 39
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 40

5 भारत में औद्योगिक वृद्धि और संभावनाएँ
[Industrial Growth and Prospects in India] 42
- ❖ औद्योगिक वृद्धि की प्रमुख विशेषताएँ 42

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पेज नम्बर

❖ भारत में औद्योगिक वृद्धि का इतिहास 42
(History of Industrial Growth in India) 42
(1) प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व की स्थिति 42
(2) सन् 1914 से 1939 तक की अवधि 42
(3) सन् 1940 से 1947 तक की अवधि 42
(4) स्वतन्त्रता के पश्चात् योजनाबद्ध विकास 43
❖ भारत में औद्योगिक वृद्धि की समस्याएँ 46
(Problems of Industrial Development in India) 46
❖ औद्योगिक वृद्धि के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम 46
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 48

6 मुद्रास्फीति : कारण, प्रभाव और उपचार
[Inflation : Causes, Effects and Remedies] 50
❖ मुद्रास्फीति का सामान्य परिचय (General Introduction of Inflation) 50
❖ मुद्रास्फीति के कारण 51
❖ मुद्रास्फीति के प्रकार (Types of Inflation) 52
❖ मुद्रास्फीति के प्रभाव (Effect of Inflation) 52
❖ मुद्रास्फीति के उपचार (Remedies of Inflation) 53
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 53

7 भारत में सार्वजनिक क्षेत्र : भूमिका, प्रगति एवं समस्याएँ
[Public Sector in India : Role, Progress and Problems] 55
❖ सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ 55
❖ भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के उद्देश्य 55
❖ भारत में सार्वजनिक उपक्रमों का उद्गम एवं विकास 56
❖ भारत के आर्थिक विकास में सार्वजनिक उद्यमों की भूमिका 56
❖ भारत में सार्वजनिक उपक्रमों का महत्त्व 56
❖ भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के दोष या समस्याएँ 57
❖ महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 के उद्योग 58
❖ भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 59
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 59

8 कृषि एवं उद्योग पर वैश्वीकरण और उदारीकण का प्रभाव
[Impact of Globalization and Liberalization on Agriculture and Industry] 61
❖ उदारीकरण (Liberalization) 61
❖ निजीकरण (Privatization) 63
❖ वैश्वीकरण (Globalisation) 63
❖ वैश्वीकरण के लाभकारी प्रभाव (Positive Effects of Globalisation) 64
❖ वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव 65
❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 66

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पेज नम्बर

9 भारतीय अर्थव्यवस्था में बहु-राष्ट्रीय निगमों की भूमिका
[Role fo Multi-national Corporation in Indian Economy] 68
- ❖ बहुराष्ट्रीय निगम का अर्थ Meaning of Multinational Corporation) .. 68
- ❖ बहुराष्ट्रीय निगमों की विशेषताएँ (Features of Multinational Corporations) 69
- ❖ भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका (Role of MNCs in India) 69
- ❖ बहुराष्ट्रीय निगमों पर सरकारी नियंत्रण (Government Control over MNCs) 71
- ❖ फेरा और फेमा (FERA and FEMA) 72
- ❖ भारत तथा बहुराष्ट्रीय निगम 72
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 73

10 विदेशी व्यापार : परिमाण, संरचना एवं दिशा
[Foreign Trade : Volume, Composition and Direction] 74
- ❖ स्वतंत्रता से पूर्व भारत का विदेशी व्यापार (Foreign Trade of India before Independence) 74
- ❖ स्वतंत्रता के पश्चात् भारत का विदेशी व्यापार (India's Foreign Trade After Independence) 75
- ❖ भारत के विदेशी व्यापार परिमाण (Volume of India's Foreign Trade) 75
- ❖ भारत के विदेशी व्यापार की संरचना (Composition of India's Foreign Trade) 76
- ❖ विदेशी व्यापार की दिशा (Direction of Foreign Trade) 78
- ❖ भारत का व्यापार शेष (Balance of Trade of India) 80
- ❖ विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 80
- ❖ भुगतान संतुलन खाता (Balance of Payment Account) 81
- ❖ विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) 83
- ❖ विदेशी आहरण अधिकार (Special Drawing Rights–SDR) 83
- ❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 83

11 राष्ट्रीय आय : अवधारणा, गणना विधियाँ और वितरण
[National Income : Concept, Computation Methods & Distribution] 85
- ❖ राष्ट्रीय आय का अर्थ 85
- ❖ राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ 85
- ❖ राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं में अंतर्संबंध 86
- ❖ राष्ट्रीय आय की साधन लागत व बाजार मूल्य की अवधारणाएँ 87
- ❖ भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 87
- ❖ राष्ट्रीय आय से संबंधित करंट आंकड़े 88
  - (1) उत्पादन विधि 88

अध्याय नं.	अध्याय का नाम ..... पेज नम्बर
	(2) आय विधि 89
	(3) व्यय विधि 89
	❖ राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली कठिनाइयाँ (Difficulties of Calculating National Income) 89
	❖ राष्ट्रीय आय का उद्योगवार वितरण 90
	❖ राष्ट्रीय आय लेखांकन 90
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 91
12	राजस्थान की अर्थव्यवस्था : मूलभूत विशेषताएँ [Economy of Rajasthan : Basic Features] 93
	❖ राजस्थान में भू-उपयोग 94
	❖ वर्ष 2022-23 में कृषि उत्पादन की स्थिति 95
	❖ कृषि के प्रकार 96
	❖ राजस्थान में कृषि फसलों का वितरण एवं उत्पादन 97
	❖ राज्य में दलहनी फसलें 97
	❖ राज्य में तिलहनी फसलें 98
	❖ व्यापारिक फसल 98
	❖ राज्य में प्रमुख बागवानी फसलें 99
	❖ राज्य में बागवानी फसलों के उत्पादक जिले 100
	❖ राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश 100
	❖ राज्य में कृषि विपणन 101
	❖ विशिष्ट कृषि उपज मण्डियाँ 101
	❖ राजस्थान में कृषि विकास कार्यक्रम एवं परियोजनाएँ 102
	❖ कृषि क्षेत्र की विभिन्न क्रांतियाँ 102
	❖ कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित अन्य प्रमुख योजनाएँ 102
	❖ राजस्थान में केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयनित फसली उत्पाद 103
	❖ महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 104
	❖ वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान एवं नवाचार ... 105
	❖ राजस्थान के प्रमुख उद्योग 106
	❖ राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योग 109
	❖ राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रमुख योजनाएँ एवं कार्यक्रम 109
	❖ दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (D.M.I.C.) 111
	❖ राज्य में औद्योगिक विकास के प्रमुख संस्थान 111
	❖ राजस्थान वित्त निगम (R.F.C) 111
	❖ राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) 111
	❖ राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसीको) 112
	❖ ग्रामीण गैर-कृषि विकास एजेंसी (RUDA) 112
	❖ राजस्थान कन्सलटेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड (RAJCON) 112
	❖ राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड 112

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पेज नम्बर

- राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड 112
- महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 113
- राजस्थान में औद्योगिक विकास के विशेष संस्थान 113
- राजस्थान में खनिजों के प्रकार 115
- राजस्थान में धात्विक खनिज 116
- राजस्थान में प्रमुख अधात्विक खनिज 117
- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (R.S.M.M.L.) 120
- महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 120
- सड़क परिवहन 122
- राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग 122
- राज्य में सड़कों से जुड़े महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम/योजनाएँ 124
- रेल-परिवहन 126
- राज्य में वायु परिवहन 127
- महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 128
- आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार आर्थिक परिदृश्य (एक नज़र में) 130
- राजस्थान के प्रमुख संकेतकों का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण 130
- महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 145

13 राजस्थान में पर्यटन का विकास
[Development of Tourism in Rajasthan] 146

- राजस्थान में पर्यटन का विकास एवं महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ 146
- राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित पर्यटन महोत्सव/उत्सव 147
- वर्ष 2022-23 में पर्यटन विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ 148
- राजस्थान के प्रमुख पर्यटन केन्द्र (जिलेवार) 148
- राजस्थान के सभी जिलों के प्रमुख पर्यटन स्थल (जिलेवार) 146
- महत्त्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर 162

14 परिशिष्ट
[Appendix] 164

- 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में श्रेणीवार पशुओं की संख्या 165
- प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्य में वनों के प्रकार 167
- राजस्थान में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत 168
- राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 168
- राजस्थान में विभिन्न साधनों द्वारा सकल सिंचित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में) 172
- पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) 172
- राजीव गांधी जल संचय योजना 172

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित

EXAM DATE : 04-12-2016

लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2013 [Re-exam]

सॉल्वड पेपर

वर्ष 2013 में विज्ञप्ति जारी हुई तथा वर्ष 2015 में परीक्षा हुई लेकिन रद्द होने की वजह से यह परीक्षा 4 दिसम्बर 2016 को आयोजित हुई।

76. वर्ष 2014-15 में भारत से सर्वाधिक निर्यात किस देश को किए गए?

(A) यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यू.एस.ए.)
(B) रूस
(C) चीन
(D) यू.ए.ई. (संयुक्त अरब अमीरात) **[A]**

व्याख्या—वर्तमान में भारत सर्वाधिक निर्यात क्रमशः अमेरिका, चीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब आदि देशों को कर रहा है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

77. भारत में रिजर्व बैंक ने बहु-नीतिगत उद्देश्यों के लिये मुद्रास्फीति की माप हेतु निम्न में से कौनसा कीमत सूचकांक अपनाया है?

(A) थोकमूल्य सूचकांक
(B) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - औद्योगिक कामगारों के लिए
(C) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - कृषि मजदूरों के लिये
(D) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त **[D]**

व्याख्या—**उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index)**

- ✧ यह **मासिक आधार** पर खुदरा कीमतों में परिवर्तन को मापता है। इसी आधार पर वार्षिक CPI की गणना की जाती है।
- ✧ इसका आधार वर्ष **2011-12** है
- ✧ CPI में **वस्तुओं** के साथ-साथ **सेवाओं** के भारांश को भी शामिल किया जाता है।
- ✧ 2014 के बाद CPI को मुद्रास्फीति के मापन का मुख्य सूचकांक बना दिया गया।
- ✧ यह सांख्यिकी क्रियान्वयन एवं कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।

78. भारत में सहकारी साख ढाँचे में निम्न से कौनसी संस्था किसानों को दीर्घकालीन साख प्रदान करती है?

(A) प्राथमिक भूमि विकास बैंक
(B) प्राथमिक कृषि ऋण दात्री समितियाँ
(C) राज्य सहकारी बैंक
(D) केन्द्रीय सहकारी बैंक **[A]**

व्याख्या—**भूमि बंधन बैंक या भूमि विकास बैंक**

- ❖ भूमि विकास बैंक किसानों की **दीर्घकालीन वित्त** की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन बैंकों का उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि को बंधक रखकर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना है। इस प्रकार के ऋण सामान्यतया 5 से 20 वर्ष की लंबी अवधि के लिये दिये जाते हैं।
- ❖ सामान्यतया किसान किसी कृषि भूमि को क्रय करने, कृषि भूमि में सुधार करने, ट्रैक्टर, थ्रैशर एवं अन्य कृषि उपकरणों को क्रय करने, खेत में ट्यूबवेल लगाने आदि उद्देश्यों के लिये अपनी भूमि को इन बैंकों के पास गिरवी रखकर दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करते हैं।

79. एन.एस.एस.ओ. के 70वें दौर के आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि साख के संदर्भ में निम्न में से कौनसा कथन सही है?

(A) कुल कृषि साख में करीब 40 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय महाजनों से प्राप्त होता है।
(B) किसानों की निधियों का 50 प्रतिशत अब भी अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त होता है।
(C) किसानों की निधियों का 40 प्रतिशत अब भी अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त होता है।
(D) किसानों को दी जाने वाली संस्थागत साख में कमी आयी है। **[C]**

व्याख्या—NSSO के 70वें दौर के आंकड़ों के अनुसार भारत में कृषि साख का 40 प्रतिशत अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त होता है। अनौपचारिक साख से अभिप्राय मित्रों, रिश्तेदारों, गैर-पंजीकृत सोसायटी, सेठ-साहूकारों आदि से लिया गया ऋण होता है। वर्तमान में औपचारिक क्षेत्र पर सरकार द्वारा ज्यादा जोर दिया जा रहा है।

80. निम्न कथनों पर ध्यान दीजिये :

कथन (A) : भारत में 2011-12 के बाद सकल जोड़े गये मूल्य (सकल घरेलू उत्पाद) में कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र में सकल पूँजी निर्माण का प्रतिशत हिस्सा गिरा है।

कथन (B) : कृषि क्षेत्र में सकल पूँजी निर्माण और सकल घरेलू उत्पाद के गिरते हुए अनुपात का कारण सरकारी क्षेत्र के विनियोगों में हुई कमी है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित

EXAM DATE : 02-08-15

लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2013

सॉल्वड पेपर

वर्ष 2013 में विज्ञप्ति जारी हुई तथा वर्ष 2015 में परीक्षा हुई लेकिन यह पेपर रद्द हो गया।

76. राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी या बहु-गणना की समस्या का समाधान किस विधि से होगा—

(A) छाया कीमतें (B) मूल्यवर्धन

(C) आरोपित मूल्य (D) नियंत्रित कीमतें **[B]**

व्याख्या—राष्ट्रीय आय की गणना की तीन विधियाँ हैं–

(i) उत्पादन (मूल्य वर्धन) विधि

(ii) आय विधि

(iii) व्यय विधि

विस्तृत व्याख्या के लिए राष्ट्रीय आय का अध्याय देखें।

77. निम्नलिखित में से कौन-सा मुद्रा-स्फीति का प्रकार नहीं है—

(A) रेंगती स्फीति (B) माँग प्रेरित स्फीति

(C) उपभोक्ता मूल्य स्फीति (D) युद्धकालीन स्फीति **[C]**

व्याख्या—मुद्रास्फीति के निम्नलिखित प्रकार होते हैं–

- रेंगती हुई/मंद मुद्रास्फीति
- अति मुद्रा स्फीति (युद्धकाल में)
- चलती हुई मुद्रास्फीति
- कोर स्फीति
- दौड़ती हुई मुद्रास्फीति
- हेडलाइन मुद्रा स्फीति
- कूदती हुई मुद्रास्फीति
- आयातित मुद्रा स्फीति
- छिपी हुई मुद्रास्फीति
- संरचनात्मक मुद्रा स्फीति

78. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति को दर्शाता है—

(A) यह पिछड़ी हुई और परम्परागत है।

(B) यहाँ निर्धन और निरक्षर लोग निवास करते है।

(C) यह अर्धविकसित तथा विकासशील है।

(D) यह अभी भी हिन्दु विकास दर के पथ पर चल रही है। **[C]**

79. निम्नलिखित में से भारत की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य कौन सा था—

(A) विकास की औसत दर 11 प्रतिशत प्राप्त करना।

(B) उच्च तथा समावेशी विकास प्राप्त करना।

(C) अंतर-राज्यीय विषमताओं को कम करना।

(D) मुद्रा स्फीति दर को 7 प्रतिशत तक सीमित करना। **[B]**

व्याख्या—11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 2007-2012 था। इस योजना में सर्वाधिक जोर अधिक तीव्र एवं ज्यादा समावेशी संवृद्धि (Faster and More Inclusive Growth) पर दिया गया था, जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक जोर 'तीव्रता धारणीय तथा अधिक समावेशीय संवृद्धि (Faster, Sustainible and more Inclusive Growth) पर दिया गया, जिसका समय वर्ष 2012-2017 तक था। 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है।

80. नाबार्ड है—

(A) विकास के लिए गैर बैंकिंग एजेन्सी

(B) सकल ग्रामीण विकास हेतु उत्तरदायी बैंक

(C) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

(D) इनमें में कोई नहीं **[C]**

व्याख्या—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD National Bank for Agriculture and Rural Development) की स्थापना **शिवरमन सिंह समिति** की सिफारिश पर **12 जुलाई 1982** को हुई थी। यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड का मुख्यालय **मुम्बई** में है।

81. भारत में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हेतु हाल ही में जो कदम उठाए गए है उनका फोकस है—

(A) व्यवसाय में आने वाले व्यवधान हटाना

(B) कौशल विकास

(C) मेक इन इंडिया

(D) उपर्युक्त सभी **[D]**

82. भारत में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुमान हेतु वर्तमान में कौन-सा आधार वर्ष है—

(A) 1990-91 (B) 2004-05

(C) 2007-08 (D) 2011-12 **[B]**

व्याख्या—वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुमान हेतु आधार वर्ष 2011-12 कर दिया गया है।

83. गत कुछ वर्षों में विश्व ने भारत सरकार की नीतियों में प्रमुख बदलाव देखे हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन कौन सा है—

(A) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ाया गया।

(B) सीमा-शुल्क (कस्टम ड्यूटी) में कमी की गई।

(C) एशिया के देशों के साथ मुक्त व्यापार में वृद्धि की गई।

लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2011

सॉल्वड पेपर

76. भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2009–10 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहायक क्षेत्र का योगदान (2004–05 की कीमत पर) रहा है—

(A) 50.2 प्रतिशत (B) 27.7 प्रतिशत
(C) 14.2 प्रतिशत (D) 14.6 प्रतिशत **[D]**

77. निम्नलिखित में से कौनसा जोड़ा राजकोषीय नीति का भाग है—

(A) सार्वजनिक आय–सार्वजनिक व्यय
(B) सार्वजनिक बजट–बैंक दर
(C) कर नीति–वैधानिक तरलता अनुपात
(D) सार्वजनिक ऋण–नकद कोषानुपात **[A]**

व्याख्या—राजकोषीय नीति क्रियान्वयन सरकार द्वारा बजटीय घोषणाओं के माध्यम से किया जाता है। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, बजट घाटे, नई मुद्रा का निर्गमन घाटे की वित्त व्यवस्था (हीनार्थ प्रबंधन) राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक होते हैं। उपर्युक्त प्रश्न में केवल (A) जोड़ा सही है। शेष के जोड़े मौद्रिक नीति के उपकरणों के साथ जोड़े गए हैं इसलिए गलत हैं।

78. निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है—

(A) 11वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास पर सर्वाधिक राशि आवंटित की गयी है
(B) 11वीं पंचवर्षीय योजना में 'अधिक तीव्र, अधिक व्यापक एवं समावेशी विकास' का लक्ष्य रखा गया है
(C) 11वीं योजना 31 मार्च, 2013 को समाप्त होगी
(D) 11वीं योजना में 'गरीबी हटाओ' का लक्ष्य रखा गया है **[B]**

व्याख्या—11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक थी। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक व्यापक एवं समावेशी विकास था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय 'सामाजिक सेवाओं' पर हुआ था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 'गरीबी हटाओ' का लक्ष्य रखा गया था।

79. निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपने विकास लक्ष्य को प्राप्त किया—

(A) द्वितीय पंचवर्षीय योजना (B) आठवीं पंचवर्षीय योजना
(C) नौवीं पंचवर्षीय योजना (D) दसवीं पंचवर्षीय योजना **[B]**

व्याख्या—8वीं पंचवर्षीय योजना को भारतीय नियोजन के इतिहास में टर्निंग प्वांइट कहा जाता है। इसके अंतर्गत 5.6 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया जिसके विपरीत 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल हुई थी।

80. भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक एवं सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है—

(i) उत्तर प्रदेश (ii) महाराष्ट्र (iii) सिक्किम (iv) मिजोरम

नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिये—

(A) (i) और (ii) (B) (ii) और (iv)
(C) (i) और (iii) (D) (iii) और (iv) **[C]**

व्याख्या— भारत के सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले चार राज्य एवं भारत की कुल जनसंख्या में उनकी प्रतिशत भागीदारी

सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य	न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य
• उत्तर प्रदेश– 199812341 (16.50%)	• सिक्किम– 610577 (0.05%)
• महाराष्ट्र– 112374333 (9.28%)	• मिजोरम– 1097206 (0.09%)
• बिहार– 104099452 (8.60%)	• अरुणाचल प्रदेश– 1383727 (0.11%)
• पश्चिम बंगाल– 91276115 (7.54%)	• गोवा– 1458545 (0.12%)

81. भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं—

(i) उच्च जन्म दर
(ii) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार
(iii) बेरोजगारी एवं गरीबी
(iv) जीवन प्रत्याशा में वृद्धि

नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिये—

(A) (i), (ii) और (iii) (B) (i), (ii) और (iv)
(C) (ii), (iii) और (iv) (D) (i), (iii) और (iv) **[B]**

व्याख्या—भारत में उच्च जन्म दर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, अशिक्षा, गरीबी, ग्रीष्म जलवायु, परम्परागत सामाजिक अंधविश्वास, संयुक्त परिवार, मनोरंजन के साधनों का अभाव, घटती हुई मृत्यु दर आदि जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं। किन्तु बेरोजगारी को जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं बल्कि परिणाम माना जाता है।

82. भारतीय कृषि के सम्बन्ध में प्रमुख तथ्य हैं—

(i) दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है

1 भारतीय अर्थव्यवस्था [Indian Economy]

विशेषताएँ एवं समस्याएँ, भारत की आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति एवं राजकोषीय नीति
[Features & Problems, Economic Policy, Industrial Policy & Fiscal Policy of India]

भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का 7वाँ सबसे बड़ा देश एवं विकासशील अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। भारत अपनी विशाल जनसंख्या एवं आर्थिक क्षेत्र में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के कारण मौजूदा दौर में क्रय शक्ति समता के आधार पर दुनिया की **तीसरी** बड़ी अर्थव्यवस्था है। जबकि GDP (Gross Domestic Product) के अनुसार भारत दुनिया की **पाँचवी** बड़ी अर्थव्यवस्था है। (हाल ही में ब्रिटेन को पछाड़ कर छठे से पाँचवे नम्बर पर आया है) भारतीय अर्थव्यवस्था को संपूर्णता में समझने हेतु इसकी विशेषताओं, चुनौतियों, आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों तथा सरकार द्वारा अपनाए गए राजकोषीय उपायों को समझना अनिवार्य है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ (Features of Indian Economy)

भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है—

(1) परम्परागत विशेषताएँ (Traditional Features)
(2) नवीन विशेषताएँ (New Features)

परम्परागत विशेषताएँ (Traditional Features)

ऐसी विशेषताएँ, जो भारत को एक अर्द्धविकसित राष्ट्र के रूप में विरासत में मिली हैं। ये विशेषताएँ भारत को एक **अविकसित अर्थव्यवस्था** के रूप में परिभाषित करती हैं, जैसे-

(1) कृषि पर अत्यधिक निर्भरता—स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 72% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह कम होकर 49% हो गया है, जबकि अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान अत्यंत कम है अतः कृषि पर अत्यधिक निर्भरता भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप का प्रतीक है।

(2) निम्न प्रति व्यक्ति आय—भारत की प्रतिव्यक्ति आय न केवल अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देशों से कम है, बल्कि चीन, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में भी कम है। प्रति व्यक्ति आय के निम्न स्तर के फलस्वरूप लोगों का जीवन स्तर भी निम्न बना रहता है।

(3) ग्रामीण अर्थव्यवस्था—वर्ष 2011 की जनगणनानुसार भारत की कुल जनसंख्या का 68.85 प्रतिशत गाँवों में निवास करता है, जो विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है।

(4) कमजोर आधारभूत संरचना—भारत में संचार परिवहन, बैंकिंग, बीमा, ऊर्जा आदि सुविधाओं का विकास कम हुआ है, औद्योगिक वित्त का अभाव है, संगठित क्षेत्र की अवसंरचना का विकास भी कम हुआ है।

Note :- आधारभूत संरचना—आधारभूत संरचना का तात्पर्य उन वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता से है, जो अर्थव्यवस्था की कार्य पद्धति को सुगम बनाते हैं। ये उत्पादकता में वृद्धि करते हैं तथा आर्थिक विकास के लिए आधार प्रदान करते हैं। सड़क, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग आदि आधारभूत संरचना के प्रमुख उदाहरण हैं।

(5) जीवन की निम्न गुणवत्ता—शिक्षा और स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता के दो सबसे प्रभावी संकेतक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में **साक्षरता** दर केवल **73%** है, यद्यपि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जन्म के समय **जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष** हो गई है किन्तु स्वास्थ्य सुविधाएँ अभी भी कमजोर हैं।

(6) अन्य परम्परागत विशेषताएँ:—

- ✧ व्यापक बेरोजगारी एवं गरीबी
- ✧ अत्यधिक आर्थिक विषमता
- ✧ असंतुलित आर्थिक विकास
- ✧ पिछड़ी हुई तकनीकी
- ✧ परम्परावादी समाज आदि

नवीन विशेषताएँ (New features)

परम्परागत विशेषताओं से यह निष्कर्ष निकालना कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है, पूर्णतया सही नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है अतः नवीन विशेषताओं के अन्तर्गत उन विशेषताओं को रखा गया है, जो इसे **विकासशील अर्थव्यवस्था** के रूप में पहचान दिलाती है, जैसे—

(1) राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में सतत् वृद्धि—

- ✧ 1950 से 1980 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर मात्र 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही, डॉ. राजकृष्णा ने इसे **'हिन्दू विकास दर'** कहा है।
- ✧ 1980 के दशक में विकास दर 5% से अधिक हो गई और 1991-2011 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था **6.8%** प्रतिवर्ष की औसत दर से बढ़ी है।
- ✧ 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान भारत की विकास दर 8% रही। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय में भी लगातार वृद्धि हुई है।
- ✧ IMF (अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष) के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक संवृद्धि दर 6.8% व 2023 के लिए 6.1% अनुमानित है। (स्रोत आर्थिक समीक्षा 2022-23)

2 भारत में नियोजन, योजना आयोग एवं नीति आयोग [Economic Planning in India, Planning Commission & NITI Aayog]

अर्थ, उद्देश्य एवं महत्त्व (Meaning, Objectives and Importance)

आयोजन का अर्थ केवल कार्य सूची बना लेने से नहीं होता और न ही यह एक राजनीतिक आदर्श है। आयोजन एक बुद्धिमत्तापूण, विवेकपूर्ण तथा वैज्ञानिक पद्धति है, जिसके अनुसार हम अपने आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं व प्राप्त कर सकते हैं। —पं. जवाहरलाल नेहरू

भारत में नियोजन का अर्थ (Meaning f Planning in India)

- प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में भारतीय योजना आयोग ने नियोजन के अर्थ को परिभाषित करते हुए लिखा-''आर्थिक नियोजन अनिवार्य रूप से सुपरिभाषित सामाजिक उद्देश्यों के अनुसार संसाधनों को अधिकतम लाभार्थ संगठित एवं उपयोग करने की एक पद्धति है, जिसके दो मुख्य संघटक हैं—
  (i) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपनाई गई व्यवस्था।
  (ii) उपलब्ध संसाधनों एवं उनके इष्टतम आवंटन के बारे में ज्ञान।
- उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि नियोजन के अन्तर्गत संसाधनों का उपयोग समाज के अधिकतम हितार्थ होता है।
- भारत में नियोजन के अन्तर्गत आर्थिक एवं सामाजिक कार्य क्षेत्रों का समावेश पाया जाता है। कृषि, उद्योग, परिवहन तथा व्यापार आर्थिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास सामाजिक क्षेत्र के मुख्य उदाहरण हैं।
- अतः ऐसा नियोजन जिसमें संवृद्धि के सामाजिक तथा आर्थिक दोनों क्षेत्रों का समावेश पाया जाए उसे 'व्यापक नियोजन' (Comprehensive Planning) कहा जाता है। यह निदेशात्मक नियोजन (Directive Planning) से अलग है। इनका अन्तर निम्न तालिका द्वारा समझा जा सकता है—

निदेशात्मक नियोजन (Directive Planning)	व्यापक नियोजन (Comprehensive Planning)
निदेशात्मक नियोजन का अर्थ उस प्रणाली से है जिसमें माँग तथा पूर्ति की शक्तियों को इस प्रकार निर्देशित किया जाता है जिससे अर्थवयवस्था में स्थायित्व अथवा संतुलन बना रहे। ऐसे नियोजन में राज्य द्वारा विकास की प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। इसमें **निजी क्षेत्र को निर्देशित** किया जाता हैं कि उसे क्या करना और क्या नहीं करना है। ताकि राष्ट्रीय हितों को कोई आँच न आए तथा **व्यक्तिगत लाभ अधिकतम** हो, निदेशात्मक नियोजन का अनुसरण केवल **पूँजीवादी अर्थव्यवस्था** में किया जाता है।	व्यापक नियोजन में सरकार स्वयं संवृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में भाग लेती है। व्यापक नियेाजन का अनुसरण **समाजवादी अर्थव्यवस्था** तथा **मिश्रित अर्थव्यवस्था** दोनों में किया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था (जैसे-भारत) में **निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह-अस्तित्व** पाया जाता है। पूंजीवाद की भाँति यहाँ व्यक्तिगत लाभ भी अधिकतम प्राप्त किए जाते हैं तथा समाजवाद की भाँति सामाजिक (सामूहिक) लाभों को प्रोत्साहित करने के लिए अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष भागीदारी होती है।

Note :- भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची (Concurrent list) में किया गया है।

नियोजन के उद्देश्य (Objectives of Planning)

नियोजन के राजनीतिक उद्देश्य-

- राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से संसाधनों का समायोजन करना।
- देश को अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत राष्ट्र के रूप में पेश करना।
- राजनीतिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना।
- आर्थिक उन्नति के जरिए वैश्विक शांति की स्थापना करना।

नियोजन के आर्थिक उद्देश्य

- संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना।
- निर्धनता एवं बेरोजगारी को दूर करना।
- राष्ट्र के आधारभूत ढाँचे का विकास करना
- पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करना।
- औद्योगीकरण, निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना।
- आत्मनिर्भरता (आर्थिक सुरक्षा) एवं आधुनिकीकरण।

नियोजन के सामाजिक उद्देश्य

- तीव्र आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास पर बल।
- सामाजिक न्याय व विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत सामाजिक समानता लाना भी नियोजन का मुख्य उद्देश्य है।
- सामाजिक सुरक्षा की स्थापना करना।

Note :- GDP में वृद्धि, पूर्णरोजगार की स्थिति, संसाधनों का न्यायोचित वितरण सुनिश्चित करना, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्राप्त करना नियोजन के दीर्घकालीन उद्देश्य हैं।

3 जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या और आर्थिक संवृद्धि के बीच संबंध [Population Explosion, Relation between Population & Economic Growth]

कारण, प्रभाव एवं उपचार (Causes, Effects and Remedies)

किसी भी देश की आर्थिक संवृद्धि उसके प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों के उचित अनुपात पर निर्भर करती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग **2.4 प्रतिशत** है, परन्तु यहाँ विश्व की लगभग **17.5 प्रतिशत** जनसंख्या निवास करती है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भू-क्षेत्रीय संसाधनों की तुलना में भारत की जनसंख्या अनुकूलतम स्तर को पार कर **विस्फोटक स्थिति** तक पहुँच गयी है और हाल ही में भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज के पोते **'फिरोज बख्त अहमद'** ने सुप्रीम कोर्ट में जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण हेतु एक जनहित याचिका दायर की है, ऐसे में जनसंख्या विस्फोट के कारण, प्रभाव व उपचारों का विस्तृत अध्ययन अनिवार्य है।

जनसंख्या विस्फोट

एक निश्चित समयावधि में किसी स्थान के निवासियों की संख्या में होने वाली तीव्र व अचानक वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाती है।

- **मौरलैण्ड** के अनुसार 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में लगभग 10 करोड़ जनसंख्या थी, जो वर्तमान में 125 करोड़ को पार कर गई है।
- भारत में प्रथम जनगणना लार्ड मेयो के समय 1872 में हुई, लेकिन यह प्रयोगात्मक रूप से कुछ ही राज्यों में हुई।
- संपूर्ण देश के लिए प्रथम जनगणना लार्ड रिपन के शासनकाल में **1881** में सम्पन्न हुई, तब से भारत में प्रत्येक 10 वर्षों के अन्तराल पर लगातार जनगणना की जा रही है।

भारत में जनसंख्या की वृद्धि/विस्फोट को समझने के लिए 1901 से 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि को चार अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है।

(1) मंद वृद्धि का काल (1901-1921)

- इस अवधि में देश की जनसंख्या की वृद्धि दर अत्यंत धीमी थी (0.27% प्रतिवर्ष)।
- **1911 से 1921** के दशक में तो देश में पड़ने वाले भीषण अकाल महामारी तथा अन्नाभाव के कारण तथा जनसंख्या में उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्युदर होने के कारण जनसंख्या में **ऋणात्मक वृद्धि दर** (–0.31%) दर्ज की गई।

(2) स्थिर वृद्धि का काल (1921-1951)

- वर्ष **1921** को भारतीय जनसंख्या विकास में एक **महान् जनांकिकीय विभाजक** कहा जाता है। इसके बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गयी।
- 1921-51 के दौरान देश की जनसंख्या में औसतन **1.45%** की दर से वृद्धि हुई, जिसका प्रमुख कारण अकाल व महामारियों पर नियंत्रण से मृत्यु दर में कमी होना तथा जन्मदर पूर्ववत् बने रहना था।

(3) तीव्र वृद्धि का काल (1951-1981)

- 1951-81 के दशकों को भारत में **जनसंख्या विस्फोट की अवधि** के रूप में जाना जाता है तथा वर्ष 1951 को **द्वितीय जनांकिकीय विभाजक** कहा जाता है क्योंकि इसके बाद जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई।
- 1951-81 के मध्य औसत 2.2% वार्षिक वृद्धि दर से जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई।
- 1961-71 के मध्य सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर (24.8%) दर्ज की गई, जो विकास कार्यों में तेजी तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण थी।
- इस अवधि में मृत्यु दर 27 प्रति हजार से घटकर 15 प्रति हजार पहुँच गई, जबकि जन्मदर में मात्र 4 प्रति हजार की गिरावट दर्ज हुई। परिणामस्वरूप जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि दृष्टिगोचर हुई।

(4) घटती वृद्धि का काल (1981-2011)

- 1981-91 में जनसंख्या की औसत वार्षिक घातीय वृद्धि 2.14 प्रतिशत थी, जो 1990-2001 में घटकर 1.95 प्रतिशत तथा 2001-2011 में 1.64 प्रतिशत रह गयी।
- अतः इस अवधि में जनसंख्या में उच्च वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रहते हुए भी वृद्धि दर में क्रमिक ह्रास दृष्टिगोचर हो रहा है। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। यह देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि जीवन की गुणवत्ता विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुई।

1901-2011 के बीच की दशकीय जनसंख्या वृद्धि

वर्ष	कुल जनसंख्या	दशकगत अन्तर कुल संख्या	वृद्धि दर (%)	औसतन वार्षिक घातीय वृद्धि (%)
1901	238396327	–	–	–
1911	252093390	(+) 13697063	5.75	0.56
1921	251321213	(–) 772117	–0.31	–0.03
1931	278977238	(+) 27656025	11.60	1.64
1941	318660580	(+) 39683342	14.22	1.33
1951	361088090	(+) 42420485	13.31	1.25
1961	439234771	(+) 77682873	21.51	1.96
1971	548159652	(+) 108924881	24.80	2.22
1981	683329097	(+) 135169445	24.66	2.20
1991	846302688	(+) 162973591	23.85	2.14
2001	1028610328	(+) 182307640	21.54	1.95
2011	1210193422	(+) 181583094	17.64	1.64

4 भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका एवं महत्त्व/कृषि वित्त के स्रोत एवं कृषि विपणन की नई प्रवृत्तियाँ

[Role and Significance of Agriculture in Indian Economy Sources of Agriculature Finance and Recent Trends in Agriculture Marketing]

भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि भारत में कृषि न केवल करोड़ों लोगों के लिए जीवन निर्वाह का साधन है बल्कि यह जीवन का तरीका भी है। स्वतन्त्रता के समय भारत को अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था किन्तु आज दुनिया का केवल 2.4% क्षेत्रफल और 4.2% पानी से ही हम विश्व की लगभग 17.5% आबादी का भरण पोषण करने में कामयाब हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है एवं निजी क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला अकेला व्यवसाय है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का **54.6 प्रतिशत** कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगा है। वर्तमान में एग्री वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन, सप्लाई चेन, डेयरी, पोल्ट्री, बागवानी, मछलीपालन इत्यादि गतिविधियों से इस क्षेत्र का महत्त्व भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका एवं महत्त्व
(Role and Significance of Agriculture in Indian Economy)

अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान

- भारत के सकल घरेलु उत्पाद में वर्ष 1950-51 में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 50 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 में यह योगदान लगभग 18.11 प्रतिशत अनुमानित है। (प्रचलित मूल्यों पर)
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3.3 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 में कृषि क्षेत्र में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए यह वृद्धि **3.5 प्रतिशत** अनुमानित है।

(स्रोत-भारत की आर्थिक समीक्षा 2022-23)

- पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है।

Note :- उपर्युक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त कृषि पशुपालन में सहयोग करती है। कृषि क्षेत्र सरकार के राजस्व अर्जन का भी अहम स्रोत है। भारत में केन्द्र व राज्य सरकारों के बजट एवं नीतियाँ भी कृषि उपज की न्यूनता या सम्पन्नता को ध्यान में रखते हुए बनानी पड़ती है।

बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये खाद्यान्नों की आपूर्ति

- भारत में कृषि क्षेत्र के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन 252 मिलियन टन रहा, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बढ़कर लगभग **315.7 मिलियन टन** हो गया है। अतः वर्तमान में भारत को अपनी विशाल जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है, बल्कि रिकॉर्ड स्तर पर खाद्यान्न निर्यात हो रहा है।

(स्रोत-भारत की आर्थिक समीक्षा 2022-23)

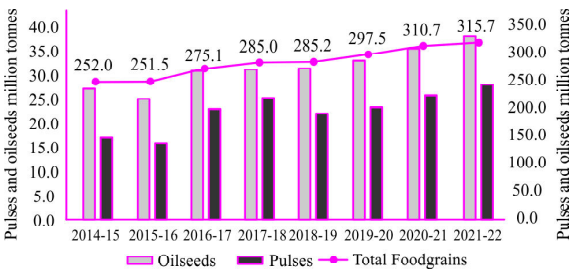

औद्योगिक विकास के लिये कृषि क्षेत्र का महत्त्व

- कच्चे माल के आपूर्तिकर्त्ता के रूप में कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि के लिये मुख्य रूप से महत्त्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र के द्वारा औद्योगिक कच्चे मालों, जैसे-कपड़ा उद्योग को कपास, तेल उद्योग को तेल, बीजों तथा चीनी उद्योग को गन्ने की आपूर्ति की जाती है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कृषि उत्पादों के रूप में कच्चा माल उपलब्ध कराता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्त्वपूर्ण योगदान

- कृषि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। भारत चाय, जूट, काजू, तंबाकू, कॉफी और मसाले आदि का निर्यात करता है। ये सभी कृषि वस्तुएँ भारत के कुल निर्यातों का एक बड़ा प्रतिशत साझा करती हैं।
- पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में, भारत से कृषि एवं संबद्ध उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया।

(स्रोत-भारत की आर्थिक समीक्षा 2022-23)

गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका सृजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका

- भारत में कृषि आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। रोज़गार अवसरों के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहने वाली भारतीय जनसंख्या का अनुपात अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे ज्यादा है।
- लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका के लिये मुख्यतः कृषि पर निर्भर है, इसमें 82 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत हैं।

पूंजी निर्माण में सहयोग

- भारत में पूंजी निर्माण प्रक्रिया में कृषि क्षेत्र का सहयोग आवश्यक है। कृषि उत्पादों के उत्पादन के रूप में तथा गैर-कृषि उत्पादों की मांग के रूप में भारत में कृषि का केंद्रीय स्थान है। गैर-कृषि उत्पादों की मांग के महत्त्वपूर्ण स्रोत होने के रूप में कृषि अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में निवेश को प्रेरित करती है।

5 भारत में औद्योगिक वृद्धि और संभावनाएँ [Industrial Growth and Prospects in India]

औद्योगिक वृद्धि से अभिप्राय उद्योगों की संख्या में वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि तथा उद्योगों में उत्पादन के तरीके में सुधार से है। औद्योगिक वृद्धि एक विकासशील देश में अधिक स्थायित्व लाने, सुरक्षा स्थापित करने और जीवन स्तर ऊँचा उठाने का महत्त्वपूर्ण साधन समझा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में, **''सभी राष्ट्र जिस देवता की आराधना करते हैं, वह देवता है औद्योगिक वृद्धि, वह देवता है मशीन, विशाल उत्पादन और प्राकृतिक शक्तियों तथा साधनों का अधिकाधिक लाभप्रद उपयोग।''**

औद्योगिक वृद्धि की प्रमुख विशेषताएँ

- औद्योगिक वृद्धि आर्थिक विकास का पर्याय है। यह अर्थव्यवस्था में रोजगार के नए-नए अवसरों का सृजन करता है।
- इसमें पूँजी का गहन एवं व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है।
- इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की संरचना में आमूलचूल परिवर्तन करना होता है।
- इससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का सामयिक एवं तीव्र विकास होता है।
- औद्योगिक वृद्धि से पूँजी निर्माण दर में वृद्धि होती है तथा क्षेत्रीय विषमताएँ कम होती हैं।
- औद्योगिक वृद्धि से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है एवं लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है।
- औद्योगिक वृद्धि उत्पादन को बढ़ाता है एवं निर्यात् को प्रोत्साहित करता है।
- औद्योगिक वृद्धि के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में स्थायित्व के साथ विकास (Growth with Stability) होता है।
- इससे देश में 'मानवीय पूँजी का विकास (Development of Human Capital) होता है, मानवीय पूँजी से अभिप्राय देश के लागों की कार्यकुशलता, शिक्षा, तकनीकी तथा वैज्ञानिक ज्ञान, स्वास्थ्य, अनुशासन आदि से है।
- औद्योगिक वृद्धि अर्थव्यवस्था में बढ़ती माँग को पूरा करने में सहायक है।

भारत में औद्योगिक वृद्धि का इतिहास

(History of Industrial Growth in India)

- भारत में औद्योगिक वृद्धि के इतिहास को निम्न चार चरणों में विभक्त किया जा सकता है।
  (1) प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व की स्थिति।
  (2) सन् 1914 से 1939 तक की अवधि।
  (3) सन् 1940 से 1947 तक की अवधि।
  (4) स्वतन्त्रता के पश्चात् योजनाबद्ध विकास।

(1) प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व की स्थिति

- 1855 से 1865 के बीच भारत में सूती वस्त्र एवं जूट के कारखाने स्थापित किए गए। 1853 में मुम्बई से थाना तक 32 किमी. लम्बी पहली रेल लाइन का निर्माण हुआ।
- 1907 में बिहार के सिंहभूम जिले के साल्वी नामक स्थान (वर्तमान जमशेदपुर, झारखण्ड) पर 'टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी' (Tisco) की स्थापना हुई।

(2) सन् 1914 से 1939 तक की अवधि

- 1914-18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ इस दौरान भारत में मित्र राष्ट्रों से आयात बंद हो गया तथा मित्र राष्ट्रों की सैनिक आवश्यकताओं में वृद्धि हुई, जिससे भारत में इस्पात, जूट व वस्त्र उद्योग को अत्यधिक लाभ हुआ।
- 1929 ई. की वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण भारतीय उद्योगों को अनेक कठिनाईयों का सामना भी करना पड़ा।

(3) सन् 1940 से 1947 तक की अवधि

- 1939 ई. में दूसरा विश्वयुद्ध प्रारंभ हो गया, युद्ध के दौरान भारत में कच्चे लोहे एवं इस्पात उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। युद्धकाल में बहुत से नए उद्योगों जैसे— एल्यूमीनियम, डीजल इंजन, पम्प, साइकिल, सोडाऐस, कॉस्टिक सोडा, सुपर फॉस्फेट, मशीन टूल्स आदि का विकास हुआ।
- भारत में हवाई जहाज बनाने का पहला कारखाना 1940 में 'हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लि.' नाम से बालचन्द्र हीराचन्द्र द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में इस कारखाने को भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में लेकर 'हिन्दुस्तान ऐरो नॉटिक्स लि.' में विलय कर दिया।
- 1945 में विश्व युद्ध समाप्त होते ही भारतीय उद्योगों के लिए पुनः कठिनाई का दौर प्रारंभ हुआ। 1947 में देश के विभाजन एवं राष्ट्रीय सरकार की स्थापना से औद्योगिक क्षेत्र में अनिश्चितता का वातावरण बना।

भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना, समय एवं स्थान

उद्योग	स्थापना वर्ष	स्थान
सूती वस्त्र	1818	फोर्ट ग्लॉस्टर (कोलकाता)
कागज़	1812	सिरामपुर (पश्चिम बंगाल)
सीमेंट	1904	चेन्नई
जूट	1855	रिशरा (पश्चिम बंगाल)
लौह-इस्पात	1874	कुल्टी (पश्चिम बंगाल)
एल्युमीनियम	1937	जे.के. नगर (पश्चिम बंगाल)
भारी इंजीनियरिंग	1958	राँची (झारखंड़)

6 मुद्रास्फीति : कारण, प्रभाव और उपचार [Inflation : Causes, Effects and Remedies]

मुद्रास्फीति का सामान्य परिचय (General Introduction of Inflation)

जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की दीर्घकाल में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होने लगती है तो वह **'मुद्रास्फीति की अवस्था'** कहलाती है। ऐसी अवस्था में कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, जबकि क्रयशक्ति (मुद्राकों मूल्य) में लगातार गिरावट होती है।

मुद्रा स्फीति **व्यापार चक्रों का एक भाग** है। प्रायः संवृद्धि की प्रक्रिया में इसे एक गंभीर बाधा माना जाता है।

उदाहरण—यदि 1 जनवरी 2023 को एक व्यक्ति ₹10 में 5 केले क्रय करता है, लेकिन अगले माह 1 फरवरी 2023 को 5 केले खरीदने के लिए उसे ₹15 खर्च करने पड़े या वह ₹10 में केवल 4 केले ही क्रय कर सका तो ऐसे में वस्तु (केले) के मूल्य में वृद्धि एवं मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी प्रदर्शित होती है, इसे ही मुद्रास्फीति कहा जाता है।

Note :– अस्थायी तथा छिटपुट मूल्य स्तर की वृद्धि को मुद्रास्फीति नहीं माना जा सकता। मुद्रास्फीति को हमेशा बुरा नहीं माना जाता उदाहरणस्वरूप मंदी के दौरान सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी को स्फीतिकारी नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके परिणाम अर्थव्यवस्था के लिए हानिकार नहीं होते।

मुद्रा अपस्फीति (Deflation)

यह मुद्रास्फीति से ठीक विपरीत स्थित होती है। इस स्थिति में कीमतें लगातार गिरती रहती हैं एवं उत्पादन व मुद्रा का मूल्य बढ़ता रहता है।

Note :– मूल्य में प्रत्येक गिरावट अवस्फीति नहीं होती है। अवस्फीति में मुद्रास्फीति की दर शून्य से नीचे (नकारात्मक) होती है।

मुद्रा विस्फीति (Disinflation)	मुद्रा संस्फीति (Reflation)
यह मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगने की अवस्था है, जिसमें कीमतों को धीरे-धीरे घटाकर सामान्य स्तर पर लाया जाता है।	यह मुद्रा अवस्फीति (Deflation) पर नियंत्रण लगाने की अवस्था है जहाँ नीचे गिरी हुई कीमतों को बढ़ाकर धीरे-धीरे सामान्य स्तर पर लाया जाता है।
यह सरकार के राजकोषीय एवं मौद्रिक उपायों का एक भाग है।	यह भी सरकार के राजकोषीय एवं मौद्रिक उपायों का एक भाग है।

मंदीगत मुद्रास्फीति (Stagflation)	स्क्यूफ्लेशन (Skewflation)
जब अर्थव्यवस्था में **मंदी** एवं **स्फीति** दोनो स्थितियाँ साथ-साथ हो अर्थात् बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति दोनो एक साथ हो तो वह Stagflation कहलाता है।	जब अर्थव्यवस्था में एक साथ **मुद्रास्फीति** और मुद्रा संकुचन (Deflation) की स्थिति हो तो वह स्क्यूफ्लेशन कहलाता है।
इसे **नियंत्रित करना चुनौतिपूर्ण** होता है। क्योंकि विस्तारक एवं संकुचित दोनों **राजकोषीय उपाय** साथ-साथ करने पड़ते हैं।	ऐसी स्थिति में **कुछ क्षेत्रो** में तो कीमत स्तर में **भारी वृद्धि** देखी जाती है एवं **कुछ क्षेत्रों** में कीमत स्तर में **गिरावट** होती है।
Stayflation = **मंदी** + **मुद्रास्फीति**	स्क्यूफ्लेशन = **मुद्रास्फीति** + **मुद्रा संकुचन/अपस्फीति**

धारणीय मुद्रास्फीति :– ऐसी दर जिससे अर्थव्यवस्था एक उच्च विकास दर पर गतिमान रहती है तथा आम लोगों को भी कोई विशेष समस्या नहीं होती है। **भारत** जैसे विकासशील देशों के लिए लगभग **5-6%** की मुद्रास्फीति को धारणीय मुद्रास्फीति कहा जाता है, जबकि विकसित देशो के लिए लगभग 2% की **मुद्रास्फीति** धारणीय मानी जाती है।

फिलिप्स वक्र

- न्यूज़ीलैण्ड के अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स द्वारा प्रतिपादित
- ''यह मुद्रास्फीति की दर तथा बेरोजगारी: दर के बीच **व्युत्क्रमानुपाती संबंध** को दर्शाता है।''

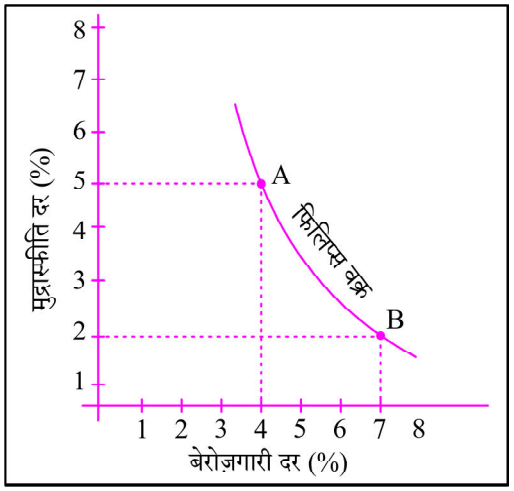

8 कृषि एवं उद्योग पर वैश्वीकरण और उदारीकण का प्रभाव [Impact of Globalization and Liberalization on Agriculture and Industry]

1950 से 1990 की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था का प्रबंधन अकुशल रहा, जिसके कारण 1990 में भारत के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, जिसका सामना करने के लिए भारत सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति को लागू किया। नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण करना है। अर्थव्यवस्था में LPG की नीति लागू करने के बाद विगत तीन दशकों में व्यापक परिवर्तन आए हैं। इस अध्याय में हम कृषि एवं उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव को समझेंगे किन्तु उससे पहले उदारीकरण एवं वैश्वीकरण का अर्थ समझना आवश्यक है।

उदारीकरण (Liberalization)

- उदारीकरण से अभिप्राय ''सरकार द्वारा व्यावसायिक इकाइयों पर लगाए गए प्रतिबंधों, नियंत्रणो एवं प्रशासनिक बाधाओं को कम करना तथा कार्यविधियों को आसान बनाना है।''
- उदारीकरण इस मानयता पर आधारित है कि बाजार की शक्तियाँ अर्थव्यवस्था को प्रतियोगिता संवृद्धि और विकास के पथ पर आगे बढ़ा कर ले जाएंगीं।
- 1991 से पहले अर्थव्यवस्था में उद्यमों पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाये गए थे; जैसे-औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था, वस्तुओं पर कीमत या वित्तीय नियंत्रण, आयात लाइसेंस, विदेशी मुद्रा नियंत्रण, निर्यात-आयात नीति, निवेश पर प्रतिबंध आदि।
- इन नियंत्रणों के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, अकुशलता को बढ़ावा मिला एवं उद्यमी भावना समाप्त हो गई, फलस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर कम हो गई। अतः अर्थव्यवस्था में उदारीकरण को अपनाया गया।

उदारीकरण के लिए किए गए उपाय

- **औद्योगिक लाइसेसिंग में उदारीकरण**—नयी आर्थिक नीति में नीजि क्षेत्र पर लगाए गए सख्त नियंत्रणों को उदार बनाया गया है। नई आर्थिक नीति के वर्ष 2006 के संशोधन के अनुसार अब केवल 5 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों को लाइसेंसिंग से मुक्त कर दिया गया है। ये उद्योग हैं;
  (i) शराब,
  (ii) सिगरेट,
  (iii) रक्षा उपकरण,
  (iv) औद्योगिक विस्फोटक,
  (v) खतरनाक रसायन।
- **एकाधिकारी कानून में छूट**— नयी आर्थिक नीति से पहले ऐसी कंपनियां जिनकी संपत्ति का आकार ₹ 100 करोड़ से अधिक था, उन पर MRTP अधिनियम के प्रावधान लगते थे। इन उद्यमों पर बहुत से प्रतिबंध लागू होते थे। नयी नीति में ₹ 100 करोड़ के संपत्ति आकार की सीमा को रद्द कर दिया गया है तथा MRTP अधिनियम के प्रावधानों को आसान बनाया गया है।
- वर्ष 2002 में MRTP अधिनियम को रद्द कर दिया गया है। इस अधिनियम के स्थान पर **'अधिक उदार प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002'** बनाया गया है। इससे बड़े औद्योगिक घरानों को अपने उद्यमों का आकार बढ़ाने व नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने की स्वतंत्रता मिल गई।
- **उद्योगों को विस्तार व उत्पादन की स्वतन्त्रता**—नयी औद्योगिक नीति में यदि कोई औद्योगिक इकाई, (जो लाइसेंसिंग के प्रावधान में नहीं आती) अपना आकार बढ़ाना चाहे या किसी नये उत्पाद का उत्पादन करना चाहे, तो इसके लिए उसे पूर्ण स्वतन्त्रता है। इससे भारतीय औद्योगिक इकाइयों को बड़े पैमाने की बचतें मिल सकेंगी।
- **छोटे उद्योगों की निवेश सीमा में वृद्धि**—लघु उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए इनकी निवेश सीमा को बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया था। अति लघु उद्योगों या सूक्ष्म उपक्रमों की निवेश सीमा को बढ़ाकर ₹ 1 करोड़ कर दिया गया था। वर्तमान में MSME Act 2006 में 1 जुलाई, 2020 को किये गये संशोधन के अन्तर्गत निवेश सीमा को ₹50 करोड़ तक बढ़ा दिया गया था।
- **फेरा के स्थान पर फेमा**—पहले विदेशी मुद्रा से संबंधित व्यवहारों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा 1973 में विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम (Foreign Exchange Regulation Act-FERA) बनाया गया था। इस अधिनियम में विदेशी मुद्रा संबंधी व्यवहारों पर बहुत ही अधिक प्रतिबंध लगाए गए थे।
- आर्थिक उदारीकरण व सरकार के विदेशी पूँजी के प्रति बदलते दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप फेरा को रद्द करके वर्ष 1999 में फेमा अधिनियम बनाया गया। **विदेशी विनिमय प्रबन्ध अधिनियम – फेमा (Foreign Exchange Management Act-FEMA)** के प्रावधान बहुत उदार हैं।
- **निर्यात व आयात व्यवहारों का उदारीकरण**— सरकार ने निर्यात-आयात नीति को काफी उदार बना दिया है। अब पूँजी उत्पादों, कच्चे माल व तकनीक के आयात को आसान बना दिया गया है।

9 भारतीय अर्थव्यवस्था में बहु-राष्ट्रीय निगमों की भूमिका [Role fo Multi-national Corporation in Indian Economy]

''बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वे विशाल औद्योगिक संगठन हैं, जिनकी औद्योगिक एवं विपणन क्रियाएँ उनकी शाखाओं के तंत्र के माध्यम से अनेक देशों में फैली हुई हैं एवं जो अपनी आय का कम से कम 25% विदेशों से प्राप्त करती हैं।'' बहुराष्ट्रीय निगमों का इतिहास काफी पुराना है। ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉयल अफ्रीकन कंपनी तथा हडसंस बे कंपनी कुछ प्राचीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदाहरण हैं।

बहुराष्ट्रीय निगम का अर्थ
(Meaning of Multinational Corporation)

- **संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार**—''बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे उपक्रम हैं, जिनके कार्यक्षेत्र, कारखाने, खानें, विक्रय-कार्यालय आदि दो या दो से अधिक देशों में हैं।''
- **I.B.M. कॉरपोरेशन के अध्यक्षानुसार**—''एक बहुराष्ट्रीय निगम वह है, जो (i) अनेक देशों में कार्य करता है। (ii) उन देशों में अनुसंधान, विकास तथा निर्माण का कार्य करता है। (iii) जिसका बहुराष्ट्रीय प्रबंध होता है तथा (iv) जिसकी शेयर पूँजी का स्वामित्व बहुराष्ट्रीय होता है।''
- संक्षेप में बहुराष्ट्रीय निगम वे विशाल औद्योगिक संगठन हैं जिनका प्रधान कार्यालय एक देश में होता है परन्तु वे अपनी व्यापारिक और विर्निमाणी क्रियाओं को बहुत से अन्य देशों में फैला लेती हैं, इन्हें कई नामों से पुकारा जाता है जैसे—**ट्रांसनेशनल निगम** (Transnational Corporation), **बहुराष्ट्रीय उपक्रम** (Multinational Enterprises), **अंतर्राष्ट्रीय निगम** (International Corporation) या **विश्वव्यापी निगम** (Global corporation)
- **भारत में बहुत से बहुराष्ट्रीय निगम जैसे**— हिन्दुस्तान यूनीलीवर, प्रोक्टर एंड गैम्बल, जॉनसन एंड जॉनसन, फिलिप्स, कोलगेट, सियेट, MRF, कोका-कोला, पेप्सी, LG, सैमसंग, नेस्ले, हुंडई, कैडबरी आदि कार्यरत हैं।

बहुराष्ट्रीय निगमों के विकास के कारण
(Reasons for Growth of MNCs)

विश्व निवेश रिर्पोट 2020 के अनुसार विश्व में लगभग 82000 MNCs कार्यरत हैं। इनकी वार्षिक बिक्री 31288 बिलियन US डॉलर है तथा ये निगम 82.36 मिलियन लागों को रोजगार दे रहे हैं। MNCs के तेजी से हुए विकास के निम्नलिखित कारण हैं—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति (International Image)—अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कारण MNCs के उत्पाद पूरे विश्व में बिकते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम आसानी से बड़े औद्योगिक घरानों, राष्ट्रों की सरकार के साथ सहयोग कर सकते हैं अर्थात् ये निगम किसी भी देश में, जहां भी ये उत्पादन करना चाहते हैं, वहां की सरकार या वहाँ के बड़े उद्योगपतियों के साथ सहयोग कर लेते हैं।

(2) वित्तीय श्रेष्ठता (Financial Superiority)—अपने बड़े आकार के कारण इन निगमों के पास बहुत अधिक वित्तीय संसाधन होते हैं। इससे ये निगम ऐसा कोई भी कार्य शुरु कर सकते हैं, जिसमें अधिक पूँजी की आवश्यकता हो। जबकि विकासशील देशों के घरेलू उद्योग, पूँजी की कमी के कारण अधिक पूंजी की आवश्यकता वाले उद्योग शुरू नहीं कर पाते। इसके अलावा अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि के कारण ये निगम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से वित्तीय संसाधन इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छी ख्याति के कारण MNCs को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने में मुश्किल नहीं आती।

(3) तकनीकी श्रेष्ठता (Technological Superiority)—घरेलू उद्यमियों की तुलना में MNCs के पास ज्यादा अच्छी तकनीक होती है। अतः MNCs उच्च व जटिल तकनीक वाले उद्योग भी लगा सकते हैं। अच्छी तकनीक के अभाव में विकासशील देशों में प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय साधनों का अल्प-उपयोग (Under utilization) होता है। इसके अतिरिक्त विकासशील देशों के निर्यात बढ़ाने के लिये यह जरूरी है कि इनके उत्पादों की क्वालिटी में सुधार लाया जाये। जो बिना अच्छी तकनीक के संभव नहीं है। विकासशील देशों को अच्छी तकनीक MNCs से मिल सकती है।

(4) विपणन श्रेष्ठता (Marketing Superiority)—निम्न कारणों से MNCs के पास अच्छी विपणन सुविधाएं हैं-

(i) अंतर्राष्ट्रीय छवि
(ii) अच्छी तकनीक के कारण अच्छी किस्म के उत्पाद
(iii) बहुत प्रसिद्ध ब्रांड
(iv) भरोसेमंद बाजार सूचना व्यवस्था
(v) विभिन्न देशों में नये उत्पाद शुरू करने का अनुभव
(vi) प्रभावी विक्रय-संवर्धन-कार्यक्रम

(5) अच्छी अनुसंधान व विकास सुविधाएं (Better Research and Development Facilities)— MNCs अपनी इकाई में अनुसंधान व विकास कार्यों के लिए एक विभाग बनाते हैं। इस विभाग का कार्य उत्पादों में निरन्तर सुधार करना है। इस विभाग के कारण MNCs अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार करते रहते हैं और उत्पादन के नये तरीके खोज लेते हैं। ऐसा करने से उनकी प्रति इकाई लागत कम हो जाती है और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होता रहता है। अनुसंधान और विकास कार्य में किये गये निवेश से यह निगम अन्य प्रतियोगी इकाइयों से कई आगे निकल जाते हैं।

10 विदेशी व्यापार : परिमाण, संरचना एवं दिशा [Foreign Trade : Volume, Composition and Direction]

"प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। रोबर्टसन के अनुसार, "विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है।" विदेशी व्यापार के उचित नियंत्रण एवं संचालन द्वारा रोजगार, उत्पादन, कीमत, औद्योगिकीकरण तथा देश के आर्थिक विकास पर उचित प्रभाव डाला जा सकता है।

विदेशी व्यापार के अंतर्गत मुख्यतः विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं, सेवाओं व साधनों के आदान-प्रदान का अध्ययन किया जाता है। उदाहरणस्वरूप भारत व अमेरिका के बीच होने वाला व्यापार **विदेशी व्यापार** है। भारत से अमेरिका को जो सामान भेजा जायेगा, उसे भारत का **निर्यात (Export)** कहा जाएगा। इसके विपरीत भारत, अमेरिका से जो सामान मंगवाएगा, उसे भारत का **आयात** (Import) कहा जाएगा।

स्वतंत्रता से पूर्व भारत का विदेशी व्यापार
(Foreign Trade of India before Independence)

- प्राचीनकाल से ही भारत का व्यापार अनेक देशों के साथ होता रहा है। 1918 के औद्योगिक आयोग के अनुसार ईसा के 3000 वर्ष पूर्व भी भारत रोम, मिश्र, चीन, मध्यपूर्वी देशों से व्यापार करता था। भारत इन देशों को कच्चा रेशम, मलमल, वस्त्र, गरम मसाले आदि का निर्यात करता था। बदले में बुलियन (सोना-चाँदी) का संकेद्रण भारत में होता था। इसी कारण भारत 'सोने की चिड़िया' कहलाता था।
- स्वतंत्रता से पूर्व भारत का व्यापार एक उपनिवेश एवं कृषि देश के रूप में था। भारत ब्रिटेन को कच्चे माल का निर्यातक एवं तैयार माल का आयातक था।
- स्वतंत्रता से पूर्व भारत के विदेशी व्यापार का अध्ययन निम्नलिखित चार बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है –

(1) व्यापार परिमाण (Volume of Trade) – स्वतंत्रता से पहले भारत का विदेशी व्यापार बहुत अधिक नहीं था। सन् 1834 में भारत का कुल विदेशी व्यापार ₹186 करोड़ था।

- सन् 1939 में यह बढ़कर ₹321 करोड़ हो चुका था तथा 1947-48 में कुल व्यापार ₹792 करोड़ था, जिसमें ₹403 करोड़ का निर्यात तथा ₹389 करोड़ का आयात था।

(2) विदेशी व्यापार का स्वरूप (Composition of Foreign Trade) – स्वतंत्रता से पूर्व भारत का विदेशी व्यापार बहुत कम वस्तुओं में होता था। भारत से कच्चे माल और कृषि वस्तुओं का निर्यात किया जाता था।

- भारत के निर्यातों में मुख्य स्थान सूती वस्त्र, कपास, अनाज, जूट की वस्तुओं, चाय और तिलहन का था।
- इस अवधि में दूसरे देशों से अधिकतर उपभोग की तैयार वस्तुएँ, मशीनें, रासायनिक पदार्थ तथा लौह और इस्पात की वस्तुएँ आयात की गईं।
- द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत के निर्यात तथा आयात के स्वरूप में परिवर्तन आया। वर्ष 1938-39 में कच्चे माल का निर्यात में भाग 45 प्रतिशत था, जो वर्ष 1947-48 में घटकर 31 प्रतिशत रह गया। वर्ष 1938-39 तैयार किये गये सामान का निर्यात कुल निर्यात का 30 प्रतिशत था, जो 1947-48 में बढ़कर 49 प्रतिशत हो गया।

(3) व्यापार की दिशा (Direction of Trade) – स्वतंत्रता से पूर्व भारत का अधिकतर व्यापार इंग्लैण्ड तथा राष्ट्रमंडल के देशों के साथ होता था। कुल निर्यात का 34 प्रतिशत तथा कुल आयात का 31 प्रतिशत व्यापार इंग्लैण्ड के साथ था। इसके अतिरिक्त दूसरे ब्रिटिश उपनिवेशों; जैसे – बर्मा, कनाडा, श्रीलंका आदि से निर्यात व्यापार 21 प्रतिशत और आयात 10 प्रतिशत (कुल में हिस्सा) था।

- इस अवधि में अमेरिका का भारत के कुल आयात में हिस्सा 7 प्रतिशत तथा निर्यात में 8 प्रतिशत था।
- सन् 1947-48 में भारत के आयात व्यापार में इंग्लैण्ड का हिस्सा कम होकर 25 प्रतिशत रह गया तथा अमेरिका का बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया। रूस तथा अन्य पूर्वी यूरोप के देशों का विदेशी व्यापार में हिस्सा बहुत कम था।

(4) व्यापार शेष (Balance of Trade) – स्वतंत्रता से पूर्व भारत का विदेशी व्यापार **बचत** (Surplus) का व्यापार था। इस अवधि में हमारे निर्यात, आयातों से अधिक रहे। वर्ष 1939 में ₹17 करोड़ का, वर्ष 1946-47 में ₹31 करोड़ का व्यापार शेष अनुकूल था। परंतु 1947-48 में यह कम होकर केवल ₹14 करोड़ रह गया।

Note :– स्वतंत्रता से पूर्व भारत का विदेशी व्यापार अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नीति पर आधारित था। इस नीति का उद्देश्य यही था कि भारत को केवल एक कच्चे माल की पूर्ति करने वाला देश बनाए रखा जाए, जिसमें इंग्लैंड के कारखानों में बना हुआ माल बेचा जा सके। अंग्रेज सरकार भारत के विदेशी व्यापार को बचत का व्यापार बनाये रखने के पक्ष में थी, क्योंकि इसके फलस्वरूप भारत को जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी, उसका उपयोग भारत के प्रशासन के लिए इंग्लैंड द्वारा किये गये खर्च (Home Charges) का भुगतान करने के लिए किया जाता था।

11 राष्ट्रीय आय : अवधारणा, गणना विधियाँ और वितरण [National Income : Concept, Computation Methods & Distribution]

राष्ट्रीय आय का अर्थ

राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था (देश) की आर्थिक निष्पादकता का मौद्रिक माप है अर्थात् किसी देश में एक वित्त वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि राष्ट्रीय आय देश के उत्पादन के सभी साधनों की आय का योग होती है न कि देश के व्यक्तियों की आय का।

Note :–
- ✧ **वित्त वर्ष**–भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।
- ✧ **अंतिम वस्तु/सेवा**–जिसका उत्पादन की प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जाता है।

❖ राष्ट्रीय आय की गणना एक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नांकित दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होती है—
- (A) राष्ट्रीय आय से राष्ट्र की आर्थिक स्थिति तथा आर्थिक प्रगति का ज्ञान होता है।
- (B) राष्ट्रीय आय के आधार पर हम विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना कर सकते हैं।
- (C) इससे अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान एवं उनके सापेक्षिक महत्त्व की जानकारी मिलती है।
- (D) राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर अर्थव्यवथा के लिए भावी नीतियों का निर्माण किया जा सकता है।

राष्ट्रीय आय की परिभाषाएँ

❖ **मार्शल**—"किसी देश के श्रम व पूंजी प्राकृतिक साधनों के साथ मिलकर एक वर्ष में जो शुद्ध भौतिक व अभौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं; उसमें विदेशी विनियोग से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाए तो उसे वार्षिक आय या राष्ट्रीय लाभांश कहेंगे।

❖ **फिशर**—राष्ट्रीय आय के अन्तर्गत केवल उन वस्तुओं व सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो उपभोक्ता को अपने वातावरण से मिली है।

Note :– फिशर ने कुल उत्पादन की बजाय उपभोग में लिए गए उत्पादन को ही राष्ट्रीय आय माना है। अतः फिशर की परिभाषा आर्थिक कल्याण को प्रधान मानती है।

❖ **पीगू**—"राष्ट्रीय लाभांश (आय) किसी समाज (देश) की वस्तुगत आय का वह भाग है" जिसमें
- (i) विदेशों से प्राप्त आय शामिल हो
- (ii) जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है।

❖ **साइमन कुजनेट्स**—"राष्ट्रीय आय वस्तुओं व सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है, जो एक वर्ष में देश की उत्पादन प्रणाली में अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचती है या पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि करती है।"

❖ **कीन्स**—इन्होंने सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) को राष्ट्रीय आय नहीं माना।

कीन्स के अनुसार—

राष्ट्रीय आय = सकल राष्ट्रीय उत्पाद – प्रयोग लागत – पूरक लागत

Note :– कीन्स ने मूल्यह्रास को ही प्रयोग लागत कहा है।

राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ

राष्ट्रीय आय के अनेक रूप होते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ कहा जाता है। एक-दूसरे से पृथक होते हुए भी ये अवधारणाएँ एक अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने हेतु अत्यंत उपयोगी हैं। राष्ट्रीय आय को समझने हेतु निम्नलिखित 4 अवधारणाओं को समझना अनिवार्य है—

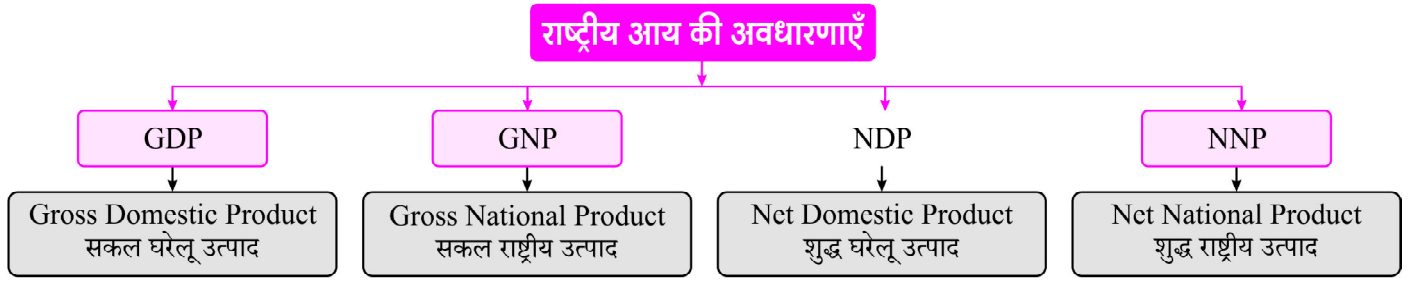

GDP (सकल घरेलू उत्पाद)

❖ किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य GDP कहलाता है। चाहे वह उत्पादन घरेलू नागरिकों/इकाइयों द्वारा किया गया हो या विदेशी नागरिकों/इकाइयों द्वारा।

Note :– यहाँ घरेलू सीमा का अभिप्राय भौगोलिक संप्रभूता से है। इसके अन्तर्गत देश की भौगोलिक, राजीनीतिक तथा सामुद्रिक सीमा, वायुमण्डल/अंतरिक्ष, शेष विश्व में सीमांतर्गत विदेशी अंतःक्षेत्र जैसे- दूतावास, सैनिक अड्डे आदि शामिल होते हैं।

12 राजस्थान की अर्थव्यवस्था : मूलभूत विशेषताएँ [Economy of Rajasthan : Basic Features]

स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योजनाबद्ध विकास का प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में राजस्थान देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकासशील राज्य के रूप में उभरा है। अतः राज्य की अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं का सम्पूर्णता में अध्ययन आवश्यक है। इस अध्याय में राज्य के योजनाबद्ध आर्थिक विकास, कृषि, उद्योग, खनिज, परिवहन आदि की मुख्य विशेषताओं के साथ, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 का सार, राज्य सरकार का बजट 2023-24 आदि का सविस्तार विवेचन किया गया है।

राजस्थान में योजनाबद्ध आर्थिक विकास (एक नज़र में)

राज्य में पंचवर्षीय योजनाएँ	योजना अवधि	वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये में)	विशेष विवरण
प्रथम पंचवर्षीय योजना	1951-56	54.15	राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना में **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण** को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई (31.3 करोड़) इसके बाद दूसरे नम्बर पर सर्वाधिक व्यय सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में किया गया (9.7 करोड़)।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	1956-61	102.74	इसमें भी **सिंचाई बाढ़ नियंत्रण** को सर्वोच्च प्राथमिकता (27.9 करोड़) दी गई। दूसरे नम्बर पर इस बार **ऊर्जा विकास** (15.2 करोड़) पर ध्यान दिया गया।
तृतीय पंचवर्षीय योजना	1961-66	212.70	**सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण** पर सर्वाधिक व्यय (87.9 करोड़) इसके बाद सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं (43.1 करोड़) तथा ऊर्जा पर (39.4 करोड़) खर्च किया गया।
तीन वार्षिक योजनाएँ	1966-67 1967-68 1968-69	136.76 (तीनों का कुल व्यय)	1962 में भारत-चीन युद्ध एवं 1965 में भारत-पाक युद्ध के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना नियत समय पर प्रारम्भ नहीं हुई इसलिए वार्षिक योजनाएँ लायी गई। तीनों वार्षिक योजनाओं में **ऊर्जा विकास** को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई (46.8 करोड़)
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	1969-74	308.79	इस योजना में सर्वाधिक व्यय **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण** पर (105.3 करोड़) किया गया उसके बाद ऊर्जा (94 करोड़) एवं सामाजिक-आर्थिक सेवाओं पर (72.4 करोड़) व्यय किया गया।
पाँचवी पंचवर्षीय योजना	1974-79	857.62	इस योजना में **ऊर्जा विकास** पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया (249 करोड़) इसके बाद **सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण** (217 करोड़) तथा सामाजिक सेवाओं पर (150 करोड़) व्यय किया गया।
वार्षिक योजना	1979-80	290.19	राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक बदलाव (जनता पार्टी सरकार) की स्थिति के कारण वार्षिक योजना को स्वीकार किया गया।
छठी पंचवर्षीय योजना	1980-85	2120.45	योजनान्तर्गत **ऊर्जा विकास** पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया (566 करोड़) तत्पश्चात क्रमशः सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण एवं सामाजिक-आर्थिक सेवाओं पर व्यय किया गया।
सातवीं पंचवर्षीय योजना	1985-90	3106.18	इस योजना में **ऊर्जा विकास** (928 करोड़) पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया उसके बाद क्रमशः सामाजिक-आर्थिक सेवा एवं सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर ध्यान दिया गया।

13 राजस्थान में पर्यटन का विकास [Development of Tourism in Rajasthan]

पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान, भारत के प्रमुख आकर्षक स्थलों में से एक है तथा विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ देशी-विदेशी पर्यटकों हेतु अनेक आकर्षण के केन्द्र हैं। आँकड़ें बताते हैं कि भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु **पर्यटन विभाग** की स्थापना **1956** में की गई तथा **1989** में **मोहम्मद युनुस समिति** की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, राजस्थान ऐसा करने वाला **देश का प्रथम राज्य** बना। राजस्थान में शाही रेलगाड़ियाँ, किले, महल, हवेलियाँ, झीलें, रेत के धोरे, मंदिर, अरावली के प्राकृतिक स्थल, एडवेंचर ट्यूरिज्म आदि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के लिए रोजगार एवं राजस्व का सृजन करते हैं।

अध्ययन बिन्दु

- राजस्थान में पर्यटन का विकास महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ
- राज्य में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित उत्सव/महोत्सव
- वर्ष 2022-23 में पर्यटन में राज्य की प्रमुख उपलब्धियाँ
- राजस्थान के पर्यटन परिपथ
- राजस्थान के प्रमुख पर्यटन केन्द्र

राजस्थान में पर्यटन का विकास एवं महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ

- राजस्थान में 1956 में स्थापित '**पर्यटन विभाग**' पर्यटन की व्यवस्था हेतु राज्य सरकार की नोड़ल एजेन्सी है।
- **पर्यटन निदेशालय-1955** द्वारा पर्यटकों के आवास, परिवहन एवं साहित्य प्रकाशन की व्यवस्था की जाती है।
- राज्य में पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं विकास हेतु **1 अप्रैल 1979** को '**राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC)**' की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय-**जयपुर** है।
- RTDC का नया पर्यटन लोगो—"**राजस्थान: भारत का अतुल्य राज्य**"
- राज्य में पर्यटन गतिविधियों हेतु मानव संसाधन का विकास करने हेतु 1966 में "**राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट (रिट्टमैन)**" की स्थापना की गई, इसका मुख्यालय भी **जयपुर** में है।
- वर्ष 2000 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में '**राज्य पर्यटन सलाहकार मण्डल**' की स्थापना की गई।
- वर्ष 2001 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में '**राजीव गाँधी पर्यटन विकास मिशन**' की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य पर्यटन नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करना था।
- राज्य में पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीन **पर्यटक पुलिस स्टेशन** खोले गए हैं—**जयपुर, उदयपुर** और **जोधपुर**।
- राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक **फ्रांस** से आते हैं।
- यदि संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो **पुष्कर (अजमेर)** में सर्वाधिक पर्यटक (देशी-विदेशी) आते हैं, जबकि केवल सर्वाधिक विदेशी पर्यटक **जयपुर** में आते हैं।

Note :- कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान (नवम्बर 2022 तक) **986.32 लाख** पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया, जिनमें **983.24** लाख **स्वदेशी** एवं **3.08** लाख **विदेशी** पर्यटक शामिल हैं।

(स्रोत-आर्थिक समीक्षा 2022-23)

- राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शाही रेलगाड़ियों का संचालन निम्नानुसार किया जा रहा है—

(1) पैलेस ऑन व्हील्स

- 26 जनवरी **1982** को प्रारंभ की गई लक्जरी ट्रेन।
- **R.T.D.C** एवं भारतीय रेलवे का संयुक्त उपक्रम।
- इसका एक सप्ताह का टूर होता है, जिसका रूट निम्नानुसार है:- **नई दिल्ली**-जयपुर-सवाई माधोपुर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर-जैसलमेर-जोधपुर-भरतपुर-आगरा-**नई दिल्ली**।
- पैलेस ऑन व्हील्स का इंटिरियर डिजाइन '**पायल कपूर**' ने तैयार किया है।

(2) रॉयल्स राजस्थान ऑन व्हील्स

- 11 जनवरी **2009** को प्रारंभ की गई लक्जरी ट्रेन।
- R.T.D.C. एवं भारतीय रेलवे का संयुक्त उपक्रम।
- इसका भी एक सप्ताह का टूर होता है, जिसका रूट निम्नानुसार है—**नई दिल्ली**-जोधपुर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़-रणथम्भौर-जयपुर-खजुराहो-वाराणसी-सारनाथ-आगरा-नई दिल्ली।

Note :- **9 सितम्बर, 2020** को राजस्थान की नई **पर्यटन नीति 2020** लागू की गई। इससे पूर्व 2001 में पर्यटन नीति लायी गई थी।

14 परिशिष्ट [Appendix]

20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पशुधन की स्थिति

- राजस्थान पशुधन की दृष्टि से समृद्ध प्रांत है, यहाँ देश के कुल पशुधन का लगभग **10.60 प्रतिशत** है।
- राजस्थान सरकार द्वारा **17 फरवरी 2010** फरवरी को राजस्थान में प्रथम बार **पशुधन विकास नीति** लागू की गई।
- राजस्थान में कुल पशुधन **5 करोड़ 68 लाख** है। कुल पशुधन के हिसाब से राज्य का देश में **दूसरा** स्थान है।

(According to Livestock Census-2019)

- 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान कुल कुक्कुट (मुर्गियों) की संख्या **146.23 लाख** है, जो देश की कुल संख्या का 1.72% है।
- भारत सरकार के पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय के अधीन पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा अक्टूबर 2019 में देश की पशुगणना रिपोर्ट जारी की गई।
- राजस्थान में पशुगणना का कार्य **'राजस्व मण्डल, 'अजमेर'** द्वारा प्रति **5 वर्ष** बाद करवाया जाता है।
- नवीनतम पशुगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन **बाड़मेर** जिले में है, जबकि न्यूनतम पशुधन **धौलपुर** जिले में है।

Note :– भारत में सर्वप्रथम पशुगणना वर्ष 1919-20 ई. में की गई थी। भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 1951 ई. में पशुगणना हुई, जबकि एकीकृत राजस्थान बनने के बाद राज्य में प्रथम पशुगणना 1961 ई. में हुई थी।

- 19वीं पशुगणना 2012 के अनुसार राज्य में पशु घनत्व **169** था, जो कि 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार घटकर **166** प्रति वर्ग किमी. रह गया है।

राजस्थान में पशुधन में वृद्धि

वर्ष	कुल पशुओं की संख्या (लाखों में)	वृद्धि/कमी (लाखों में)
1951	255.21	—
1961	335.09	79.88
1972	388.78	33.69
1982	496.50	107.72
1988	409.01	–87.41
1992	484.45	75.44
1997	546.74	62.99
2003	492.43	–54.31
2007	566.63	74.20
2012	577.32	10.59
2019	568.00	–9.00

- उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में पशुधन में सर्वाधिक वृद्धि 1972-1982 के काल में 107.72 लाख दर्ज की गई।
- वर्ष 1988, 2003 एवं 2019 में क्रमशः 87.41 लाख, 54.31 लाख एवं 9 लाख पशुओं की संख्या में कमी हुई है।
- पशुगणना–2019 के अनुसार राजस्थान में देश का कुल पशुधन है—
  - (1) **7.24** प्रतिशत – गौवंश
  - (2) **12.47** प्रतिशत – भैंस
  - (3) **14.00** प्रतिशत – बकरियाँ
  - (4) **10.64** प्रतिशत – भेड़
  - (5) **84.43** प्रतिशत – ऊँट
- राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला **डूंगरपुर** (433) है। इसके बाद क्रमशः **बांसवाड़ा** (386) और **दौसा** (308) अधिक पशु घनत्व वाले जिले हैं।
- राजस्थान में सबसे कम पशु घनत्व **जैसलमेर** (62) एवं बीकानेर (90) जिलों का है।
- नवीनतम पशुगणना के अनुसार **बकरी**, **ऊँट** एवं **गधों** की संख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान देश में **प्रथम** स्थान पर है।
- राजस्थान के पशुधन का देश की G.D.P. में 10 प्रतिशत से अधिक योगदान है।

राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम पशुधन 2019 की पशुगणनानुसार

पशु का नाम	सर्वाधिक संख्या वाला जिला	न्यूनतम संख्या वाला जिला
बकरी	बाड़मेर	धौलपुर
गौवंश	(1) बीकानेर (2) जोधपुर	धौलपुर व करौली
भैंस	(1) जयपुर (2) अलवर	जैसलमेर
भेड़	बाड़मेर	बांसवाड़ा
ऊँट	जैसलमेर	प्रतापगढ़
अश्व	बीकानेर	डूंगरपुर
गधे	बाड़मेर	—
खच्चर	अलवर	—
सूअर	(1) जयपुर (2) भरतपुर	—
मुर्गी	अजमेर	—

Note :– 2012 की पशुगणना में सर्वाधिक गौवंश उदयपुर में था, जबकि 2019 के अनुसार **सर्वाधिक गौवंश बीकानेर** में है। इसी प्रकार 2012 में सर्वाधिक सूअर भरतपुर में मिलते थे, जबकि 2019 **में सर्वाधिक सूअर जयपुर** जिले में मिलते हैं।

मार्गदर्शक परिचय

M.K. Yadav
(RES)

राजस्थान कर्मचारी चयन द्वारा आयोजित Jr. Accountant & TRA भर्ती परीक्षा में सफलता हेतु 'भारतीय अर्थव्यवस्था' अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय है। इस विषय में अध्ययन-अध्यापन का श्री एम.के. यादव सर को विशद अनुभव है। आपकी लेखन कार्य में गहन रुचि है। आपके निर्देशन में तैयार ग्रेड I, II, CET, REET एवं 'राजस्थान सार संग्रह' आदि पुस्तकों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहत्तर परिणाम दिए हैं, जिससे हजारों प्रतियोगी परीक्षार्थियों ने सफलता प्राप्त की है।

जूनियर अकाउण्टेन्ट परीक्षा की विस्तृत तैयारी के लिए दक्ष प्रकाशन की अन्य पुस्तकें

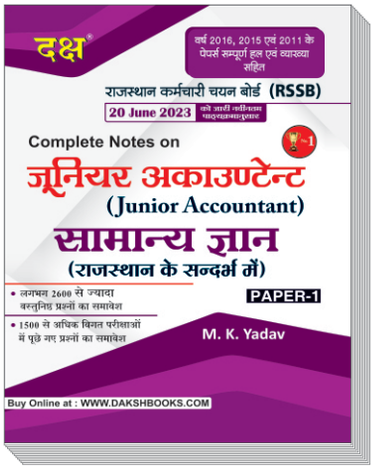

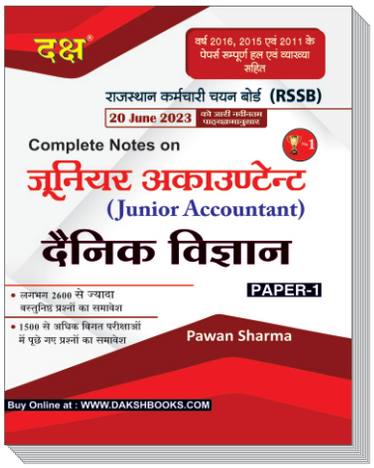

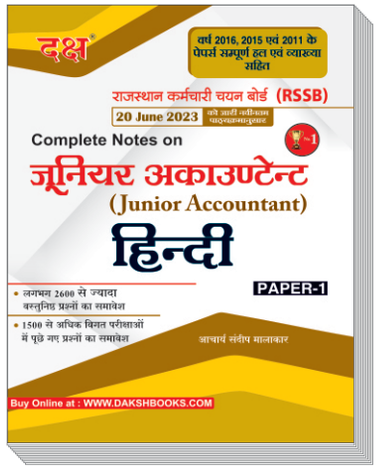

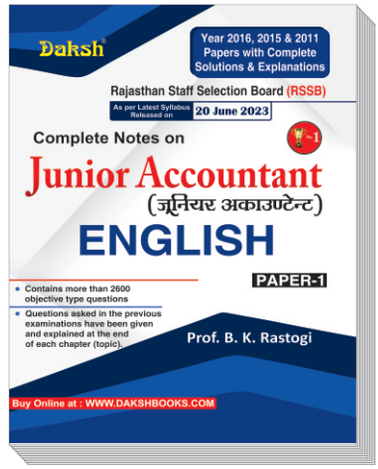

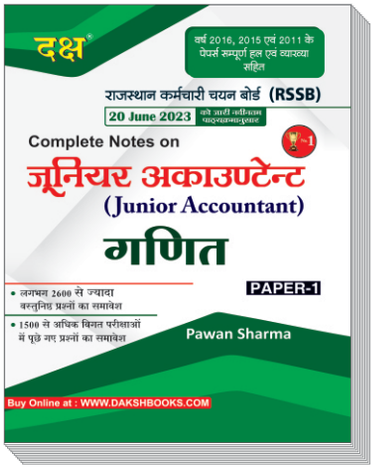

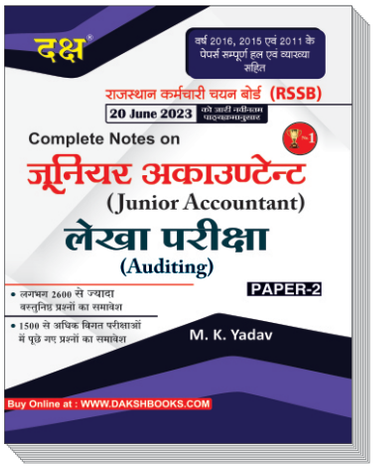

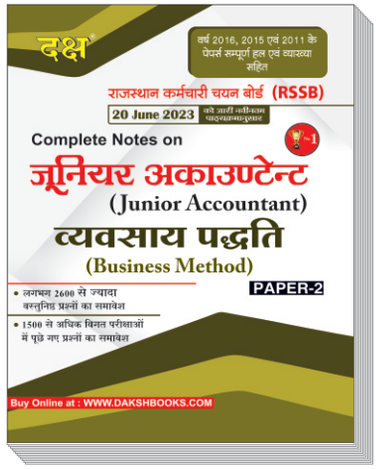

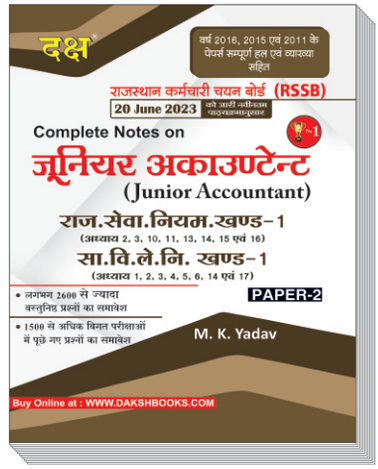

दक्ष प्रकाशन

(A Unit of College Book Centre)
A-19 सेठी कॉलोनी, जयपुर (राज.)
फोन नं. 0141-2604302
Code No. D-698 | ₹ 480/-

इस पुस्तक को ONLINE खरीदने हेतु
WWW.DAKSHBOOKS.COM
पर ORDER करें
★ SPECIAL DISCOUNT + FREE DELIVERY ★